राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 18 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-227 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को कुचला, दो की मौत, दो गंभीर

गुरुग्राम(एजेंसी)। हरियाणा के गुरुग्राम में बुधवार देर रात द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक कार ने चार लोगों को कुचल दिया। इस घटना में दो की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है। घायलों निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को बताया कि न्यू पालम विहार में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात करीब 2:30 बजे हादसा हुआ। दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक्सप्रेसवे पर ग्रिल लगा रहे चार लोगों को टक्कर मार दी। घायलों में से दो की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले, हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर बसताड़ा टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी लोग करनाल की तरफ जा रहे थे। ये लोग बाइक पर सवार थे, जिन्हें कार ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान मोहम्मद अर्श और मोहम्मद जफर के रूप में हुई। मृतकों के एक रिश्तेदार ने बताया कि वह मेरठ के रहने वाले थे। यहां मजदूरी करते थे। उन्होंने बताया कि बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि ग्रुप में फोटो शेयर हुए थे, जहां से हमने मृतकों की पहचान की, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

कर्नाटक के भटकल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, मस्जिद-मदरसे को निशाना

भटकल (एजेंसी)। (ईएमएस)। कर्नाटक के भटकल में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव से इलाके में तनाव फैल गया है। यह घटना तालांद से शुरू हुए जुलूस के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इस्माइल सुन्नी जामिया मस्जिद और ताजुल सुन्ना अरबी मदरसे के पास पहुंचने पर हुई। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर इन धार्मिक स्थलों पर पत्थर फेंकने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, गुल्मी रेलवे ब्रिज पार करने के बाद जुलूस जैसे ही मस्जिद और मदरसे के करीब पहुंचा, अचानक पथराव शुरू हुआ। इस हमले में मस्जिद और मदरसे की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे एक समुदाय में भारी आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात भटकल टाउन थाने के बाहर जमा होकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। अब्दुल अलीम और शाहुल अमीन गवाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्थिति की गंभीरता को देखकर उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपन स्वयं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करके निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। एसपी दीपन ने लोगों से सहयोग की अपील कर कहा कि पुलिस अपनी जांच जल्द शुरू करेगी और जिसने भी यह गलत काम किया है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे भटकल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की मदद से पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

लखनऊ में रिकवरी एजेंटों का आतंक! पिस्टल की नोक पर परिवार से छीनी कार

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फाइनेंस रिकवरी एजेंटों की दबंगई और गुंडई के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बीमार बच्चे का इलाज कराने पहुंचे एक परिवार को अज्ञात रिकवरी एजेंटों ने बीच सड़क पर बंधक बना लिया। पीड़ित जुबैर खान ने आरोप लगाया है कि एजेंटों ने उनकी कमर पर पिस्टल सटाकर परिवार को जबरन गाड़ी से नीचे उतारा और कार लूटकर फरार हो गए। जुबैर खान के मुताबिक, वे अपने बीमार बच्चे को दिखाने अस्पताल गए थे। ओपीडी में समय होने के कारण वे बच्चे को बाहर कुछ खिलाने निकले, तभी कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर दो-तीन किश्तें बकाया होने की बात कह दी। पीड़ित द्वारा भाई से फोन पर बात करने के बावजूद आरोपी उन्हें रिसीविंग देने के बहाने आगे ले जाने लगे। जब उन्होंने गाड़ी रोकी, तब करीब 12 अज्ञात लोगों ने उनकी कार को घेरा और पिस्टल की नोक पर धमकाते हुए पत्नी और मासूम बच्चों सहित उन्हें बीच सड़क पर उतार दिया।

आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ का मानहानि नोटिस

मुंबई(एजेंसी)। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी(एसपी) नेता अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बार एंड बेंच के मुताबिक, नोटिस में दोनों नेताओं से उनके बयानों को वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और 500 करोड़ का हर्जाना देने की मांग की गई है। दोनों को इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। आदित्य ठाकरे ने जांच में उनका नाम आने पर कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है। वहीं, अनिल देशमुख ने कहा था कि आदित्य को बदनाम किया जा रहा है।

यूसीसी के नाम पर नीतीश को भगवामय करने की तैयारी में राजद!

पटना, एजेंसी।

बिहार की सियासत में फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक बड़ी सियासी चाल चली है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, आरजेडी यूसीसी के मुद्दे पर नीतीश को लगातार कठघरे में खड़ा कर रही है और उन पर बीजेपी के दबाव में होने का आरोप लगा रही है। आरजेडी का मुख्य मकसद नीतीश के सेक्युलर छवि के आवरण को हटाकर उन्हें राजनीतिक रूप से भगवामय साबित करना है, ताकि मुस्लिम मतदाताओं का पूरी तरह से ध्रुवीकरण उनकी अपनी पार्टी के पक्ष में हो जाएं।

भले ही अभी तक यूसीसी का कोई आधिकारिक ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन आरजेडी ने मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। पार्टी नेताओं, जैसे भाई वीरेंद्र के बयानों का लब्बोलुआब यही रहा है कि यदि नीतीश वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं, तब उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेकर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनानी चाहिए। आरजेडी अच्छी तरह जानती है कि जेडीयू विधायक दल में टूट की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन इस बहस के जरिए वे अल्पसंख्यक समुदाय के मन में नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। बिहार के चुनावी समीकरणों में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में तगड़ा झटका खाने के बाद आरजेडी अब किसी भी हाल में वोट बैंक को अपने पाले में एकजुट करना चाहती है। पार्टी यह रणनीतिक खेल खेल रही है कि जितना अधिक वे यूसीसी का विरोध करेगी और नीतीश-बीजेपी गठबंधन पर हमलावार रहेगी, मुस्लिम वोटर उतने ही मजबूती से आरजेडी के साथ गोलबंद हो जाएंगे। आगामी विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों और अन्य राजनीतिक भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए आरजेडी का यह कदम उनकी सोची-समझी राजनीतिक प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे वे राज्य के सत्ता समीकरण में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं।

पीएम के जन्मदिन पर सीजेपी ने कहा- स्कूल ठीक करो...

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), जो हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के बाद से लगातार चर्चा में है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जन्मदिन पर दीया जलाने के अभियान पर सवाल उठाया है। रांका ने अपनी पोस्ट में लिखा, बताओ कल देशभर के कॉलेज को सुबह सुबह आशीर्वाद का दीया जलाने के लिए क्यों बोला गया है गाइज? बताओ कल किसका जन्मदिन है गाइज? उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस बीच, सीजेपी अपने स्कूल ठीक करो अभियान को भी गति दे रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारत में आदिवासी स्कूलों को पिछले 80 वर्षों से सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे को उजागर करने के लिए, सीजेपी 17 सितंबर से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से अपने 'आदिवासी स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत करेगी।इसका उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं और भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। यह अभियान सीजेपी के व्यापक स्कूल ठीक करो मुहिम का हिस्सा है, जिसे एक महीने पहले ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया था। इस पहल के तहत, सीजेपी प्रतिनिधि स्कूलों का दौरा कर बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करेंगे।

मनोज जरांगे ने खत्म की भूख हड़ताल, दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र के बीड जिले में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन, जो पिछले 20 दिनों से मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के चलते चर्चा में था, अब एक नए मोड़ पर आ गया है। मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। उन्होंने सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए 90 दिनों का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मराठा समुदाय द्वारा प्रस्तावित मुंबई मार्च को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। डॉक्टरों ने जरांगे पाटिल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई थी और कहा था कि अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसी बीच, बीजेपी विधायक प्रसाद लाड मुंबई से अहिल्यानगर के लिए रवाना हुए और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ पाटोदा पहुंचे, जहां यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री दादा भुसे, विधायक प्रसाद लाड, विधायक सुरेश धस और बीड के जिला कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे पाटिल ने अपनी प्रमुख मांगें दोहराईं। उन्होंने कहा कि शिंदे समिति द्वारा खोजे गए 58 लाख रिकॉर्ड में एक भी रिकॉर्ड कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने इन रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणपत्र और उनकी वैधता देने के लिए एक लिखित गारंटी और समयबद्ध कार्यक्रम की मांग की। जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि वे रिकॉर्ड खोजने के काम में अपने लोगों को भी लगाने के लिए तैयार हैं, और आरोप लगाया कि शिंदे समिति तथा सरकार इस मामले पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकार की ओर से भी कई आश्वासन दिए गए। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सातारा, कोल्हापुर, पुणे और औंध के गजट से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर तीन महीने में जीआर (सरकारी प्रस्ताव) जारी कर लागू किया जाएगा। इसके अलावा, हैदराबाद गजट के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक संशोधित जीआर लाने और इन प्रमाणपत्रों को वैधता देने की प्रक्रिया जारी रखने का आश्वासन दिया गया। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिंदे समिति को मिले 58 लाख रिकॉर्ड कम नहीं किए जाएंगे। साथ ही, मराठवाड़ा के चार जनप्रतिनिधियों के रद्द किए गए कुनबी प्रमाणपत्रों को वैध करने की बात भी कही गई।

महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रावासों में यौन शोषण का आरोप

छात्राओं ने प्रेग्नेंसी टेस्ट की भी शिकायत की

नागपुर, एजेंसी।

महाराष्ट्र के नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आदिवासी छात्र-छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान छात्राओं ने आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां बताईं, जिसमें यौन शोषण की शिकायतें भी शामिल हैं। छात्राओं ने कई मामलों में जबरन प्रेग्नेंसी टेस्ट कराए जाने का भी आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके 17 सितंबर से आदिवासी स्कूलों का दौरा करने की एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को आदिवासी छात्राओं से भी बात की, जिन्होंने खुलकर अपनी परेशानियां बताईं। कई छात्राओं ने बताया कि अधिकांश आदिवासी आश्रम स्कूलों में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। दीपके के साथ बुधवार को हुई बातचीत में विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों की कई छात्राएं शामिल हुईं थीं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय के बच्चों को आरोपी बना दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारी आदिवासी स्कूलों में सुविधाओं की कमी भी बताई। इस दौरान एक छात्रा ने खासतौर पर भंडारा के हॉस्टल का जिक्र किया, जहां 15 लड़कियों को एक ही कमरे में रखा जाता है। कई छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि आश्रम स्कूलों में बच्चियों को जबरन प्रेग्नेंसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, वॉशरूम के इस्तेमाल और स्कॉलरशिप सहित अन्य परेशानियां भी गिनाईं। नागपुर स्थित आदिवासी विकास भवन में कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपके ने आदिवासी छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा है कि वह राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरेंगे। उन्होंने बच्चों को अपनी परेशानियों की जानकारी फैलाने और इसके लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने की सलाह दी। दीपके ने बुधवार को आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान की 17 सितंबर से शुरुआत का ऐलान किया है। इससे पहले उनकी पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान चला रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 80 वर्षों में सभी सरकारों ने देशभर के आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की उपेक्षा की है। इसलिए वे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। दीपके ने सरकारों पर आदिवासी छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपने

मुख्यालयों पर करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन आदिवासी आवासीय विद्यालयों के लिए धन नहीं है, जो अक्सर किराये की इमारतों से चलते हैं। उन्होंने सरकार से आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने की अपील की, क्योंकि केवल जीडीपी वृद्धि या अर्थव्यवस्था के आकार की बात करना पर्याप्त नहीं है।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर विवाद, सुप्रीम कोर्ट बोला-हिंदी को लेकर सोच बदलनी होगी

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार से कहा कि हिंदी को लेकर आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चेन्नई और दिल्ली को एक-दूसरे से अलग-थलग करने की सोच पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि चेन्नई में बैठे लोगों को दिल्ली में बैठे लोगों से अलग नहीं होना चाहिए और न ही दिल्ली को चेन्नई से। पूरा मामला तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोलने को लेकर है। ये केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले स्कूल हैं। यहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं और छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होती है। इन स्कूलों को नवोदय विद्यालय समिति चलाती है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। रा'य सरकार इन स्कूलों को खोलने का विरोध करती रही है। इसकी मुख्य वजह स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं। नवोदय विद्यालयों में तीन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इनमें हिंदी भी शामिल है।

हमें अमेरिकन पुलिस की तरह काम करना होगा: किरण बेदी

गुरुग्राम हिट-एंड-रन जैसे मामलों पर पूर्व आईपीएस की राय

नई दिल्ली, एजेंसी।

गुरुग्राम में हुए हालिया हिट-एंड-रन मामले पर अपनी राय रखते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि ऐसे लोगों के मन में डर पैदा करना बेहद ज़रूरी है। उनका मानना है कि जब लोग गाड़ी चलाते समय लापरवाही या जानबूझकर ऐसी खतरनाक हरकतें करते हैं, तो उन्हें इसके गंभीर नतीजों से डरना चाहिए, जैसे गाड़ी और लाइसेंस छिन जाना, हथकड़ी लगना, जेल जाना, सज़ा भुगतना, भारी जुर्माना भरना और सबके सामने बेइज़्ज़ती होना। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि आरोपी आदमी एक महिला को अपने साथ तेज रफ्तार में चलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि एक महिला उसके साथ बराबरी कर रही है, और अपना दबदबा दिखाने के लिए उसने महिला का रास्ता काटा। अगर लड़की की मोटरसाइकिल पर कैमरा नहीं होता, तो शायद हमें इस घटना के बारे में कभी पता ही नहीं चलता।

किरण बेदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी हरकतें होती रही हैं और होती रहेंगी, जब तक कि हम डर को नहीं बढ़ाते। उन्होंने कहा कि इन लोगों में डर की कमी है, और हमें यह डर पैदा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि डर पैदा कैसे करें? बेदी के अनुसार, हमें ऐसे लोगों को पकड़ने की संभावनाओं को बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है कि अब हमें तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आजकल कैमरे हमें अपराधों को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। अभी सामान्य अपराध के लिए ट्रैफिक पुलिस कैमरे का उपयोग कर रही है, नंबर नोट करती है और घर पर ई-चालान आ रहा है। लोगों को डर हो रहा है कि कैमरा पकड़ लेगा। हाईवे पर स्पीड की समस्या है, हमें यहां भी कैमरे लगाने होंगे। किरण बेदी ने बताया कि अमेरिकन पुलिस यही करती है; उनके पास इंटरसेप्टर्स होते हैं जो पीछे से आते हैं और पता भी नहीं चलता। वे तुरंत हथकड़ी लगाते हैं ताकि अपराधी कोई हरकत न कर पाए। उसके बाद उसकी गाड़ी, उसकी चाबी, उसका लाइसेंस सब ले जाते हैं। फिर पूछते हैं कि अब बताओ, तुम कैसे कर रहे हो ये हरकत? उन्होंने कहा कि जब तक हम डर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी हरकतें होती रहेंगी। ये डरे हुए नहीं हैं, इसीलिए तो अपनी मनमर्जी करते हैं। गुरुग्राम वाले मामले में एक बात तो साफ है कि वह आदमी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे पसंद नहीं आया कि एक औरत उसके साथ बराबरी करे, उसे लगा मैं आदमी हूं, तू कौन है। यहां मानसिकता वाली बात है। उसे लगा कि एक औरत कैसे उसकी बराबरी कर सकती है।

टीएमसी का नाम-निशान फीज कर सकता है चुनाव आयोग

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, लेकिन संभावना है कि वे तृणमूल कांग्रेस के नाम और मौजूदा चुनाव चिह्न के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर खींचतान तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख बुधवार को थी, इसी दिन चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को पत्र भेजकर दोपहर 3 बजे तक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को कहा।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बताया कि ऐसे मामलों में फैसला लेने में समय लगता है। अगर चुनाव नजदीक हो तो आयोग आमतौर पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज कर देता है। इसके बाद दोनों गुटों को अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने भी इसी संभावना से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आम तौर पर आयोग चुनाव चिह्न को फ्रीज करता है और इसके लिए कई स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।चुनाव आयोग दोनों गुटों से अतिरिक्त दस्तावेज मांग चुका है। आयोग दोनों पक्षों को एक बार फिर सुनवाई के लिए बुला सकता है। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमां ने बताया कि आयोग ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था और उन्हें यह भी बताया गया कि गुरुवार को एक और सुनवाई हो सकती है। उनके मुताबिक, चुनाव चिह्न का आवंटन 19 सितंबर तक पूरा होना जरूरी है। पिछले शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी पीठ ने दोनों गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। एक गुट का नेतृत्व तृणमूल की संस्थापक और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं। दोनों गुटों ने आयोग से अपील की थी कि उपचुनाव से पहले तृणमूल के चुनाव चिह्न और पार्टी की संपत्तियों पर दावों को लेकर फैसला किया जाए। ममता बनर्जी के करीबी एक तृणमूल नेता ने आयोग पर जानबूझकर जटिलताएं पैदा करने का आरोप भी लगाया।

भतीजे-समधी को पार्टी से निकालने के बाद परिवारवाद को लेकर मायावती कंफ्यूज?

-पहले भतीजे को बसपा में सेट करने में लगी रहीं, अब भतीजी की कराना चाहती हैं एंट्री

नई दिल्ली,, एजेंसी।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद और समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद राजनीति में परिवारवाद पर बड़े दावे किए हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह बसपा संस्थापक कांशीराम की तरह परिवारवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कांशीराम की शिष्या होने के नाते परिवारवाद पर उनकी तरह ही डंटी हुई हैं।

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी में लेकर आईं। आकाश को पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके साथ ही पार्टी को मैसेज चला गया कि मायावती बसपा की कमान आकाश आनंद को ही सौपेंगी। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में ही पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। 2026 अगस्त में एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद को लॉन्च किया गया, लेकिन उनकी दो रैलियों के बाद ही उन्हें पार्टी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इससे मैसेज मिलता है कि मायावती अपने भतीजे आकाश को पार्टी में सेट करने का प्रयास करती रहीं, लेकिन अब जब वह उन्हें बाहर कर चुकी हैं, तो पार्टी में परिवारवाद नहीं होने की बात कह रही हैं।

मायावती एक तरफ जहां कहा है कि उनके छोटे भाई आनंद कुमार के दोनों बेटों आकाश आनंद और ईशान आनंद को अब बीएसपी में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मायावती यह भी कह रही हैं कि आनंद कुमार चाहे तो अपनी इकलौती बेटी कुमारी दीपिका आनंद को पार्टी में जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। हालांकि वह यह भी कह रही हैं कि लॉ की पढ़ाई कर रहीं दीपिका की ईमानदारी की परख की जाएगी।

मायावती खुद के महिला होने की बात को आगे कर परिवारवाद पर रियायत मांग रही हैं। कह रही हैं कि उन्होंने शादी नहीं की इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को अपने साथ रखा, जो कि उनकी देखभाल के साथ पार्टी का भी काम देखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब मायावती जैसी ताकतवर नेता खुद स्वीकार कर रही हैं तो सवाल यह है कि वह फिर किस हैसियत से नारियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे पाएंगी। एक सवाल यह भी उठता है कि अगर मायावती परिवारवाद के खिलाफ रहीं तो उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की शादी के लिए पार्टी के सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी को क्यों चुना।

हाल ही में यूपी बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का असामयिक निधन हो गया था। उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची मायावती ने कहा था कि उनके इकलौते बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगी। इसके बाद लखनऊ में हुई बैठक में उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश अग्रिम पंक्ति में बैठे दिखे। अब सवाल उठता है कि जब मायावती पार्टी में किसी भी स्तर पर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो भला वह प्रिंस युकेश को किस हैसियत से चुनाव

में टिकट देने का मन बना रही हैं, जबकि युकेश अब तक किसी भी राजनीतिक कार्यों में खास सक्रिय नहीं रहे हैं।

परिवारवाद को लेकर मायावती के इन फैसलों को देखने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो मायावती पिछले दो साल से भतीजे को पार्टी की कमान सौंपने की पूरी प्लानिंग कर रही थीं, उन्हें अचानक से कांशीराम के सिद्धांत कहां से याद आ गए। अगर वाकई वह परिवारवाद के खिलाफ हैं तो उनके भाई आनंद कुमार अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसे हैं। इसके अलावा मायावती की भतीजी कुमारी दीपिका को पार्टी में अभी से लाने की इजाजत अभी से क्यों दे रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सेमीकॉन इंडिया 26 सिलिकॉन से सिस्टम तक विकसित भारत 2047 की नई उड़ान

(लेखक – विनोद सिंह 'तकियावाला')

युवा इंजीनियरिंग,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,सेमीकंडक्टर और विनिर्माण के संगम से बदल रही भारत की अर्थव्यवस्था; प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – नीति से आगे बढ़कर अब भारत में बन रहे हैं चिप और वैश्विक बाजार तक पहुँच रही है, भारतीय तकनीक

वैश्विक मानचित्र पर किसी देश की आर्थिक शक्ति का आकलन केवल उसकी सड़कों,रेल लाइनों, बंदरगाहों,गगनचुंबी इमारतों या डिजिटल नेटवर्क से नहीं होता। बल्कि आज के बदलते परिवेश में उस देश की असली ताकत इस बात से भी तय होती है कि वह नवीन तकनीकों का निर्माण कितना कर सकता है,जो इन सभी व्यवस्थाओं को संचालित करती हैं।आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर ऐसी ही बुनियादी तकनीक बन चुका है।मोबाइल फोन से लेकर रेलवे, ऑटोमोबाइल,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण,रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष तकनीक और डेटा सेंटर तक शायद ही कोई आधुनिक क्षेत्र हो,जिसकी कार्यप्रणाली चिप के बिना पूरी हो सके।इसी बदलती वैश्विक तकनीकी व्यवस्था के बीच नई दिल्ली का यशोभूमि इन दिनों केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं,बल्कि भारत की भावी आर्थिक और तकनीकी दिशा का साक्षी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2026 के पाँचवें संस्करण का उद्घाटन किया। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस इ सेमीकॉन इंडिया 2026 का विषय है—'सिलिकॉन से सिस्टम तक ‑ इकोसिस्टम का निर्माण'। 52 देशों की भागीदारी, 600 से अधिक प्रदर्शक,150 से अधिक वक्ता छह देश मंडप और 12 राज्य मंडप इस आयोजन को वैश्विक तकनीकी संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना रहे हैं। सर्व विदित रहे कि सेमीकॉन इंडिया 2026 का महत्व केवल इसकी भव्यता और वैश्विक भागीदारी में नहीं है।इसका वास्तविक महत्व उस परिवर्तन में छिपा है,जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन संबोधन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब परियोजनाओं की घोषणा और निर्माण के चरण से आगे बढ़कर वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुँच गई है।उनके अनुसार पहले सेमीकॉन आयोजन में नीतियों पर चर्चा हुई,फिर परियोजनाओं और शिलान्यास की बात आई,पिछले वर्ष पायलट लाइन और टेस्ट चिप की चर्चा हुई और अब भारतीय संयंत्रों से तैयार चिप ग्राहकों तक पहुँचने लगी है।यही बदलाव विकसित भारत 2047 की बड़ी तस्वीर को समझने की कुंजी भी है।भारत ने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मुख्यत: उपभोक्ता बाजार के रूप में अपनी पहचान बनाई। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक भारत में खपत तेजी से बढ़ी,लेकिन उसके पीछे लगने वाली चिप तकनीक का बड़ा हिस्सा बाहर से आता रहा।आज तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है।अब लक्ष्य केवल चिप का इस्तेमाल करना नहीं,बल्कि उसके डिजाइन से लेकर निर्माण,पैकेजिंग, परीक्षण, उपकरण,सामग्री और अंततः चिप से तैयार सिस्टम तक पूरी मूल्य श्रृंखला को भारत में मजबूत करना है।इसीलिए इस वर्ष का 'सिलिकॉन से सिस्टम तक' विषय अपने भीतर एक बड़ी आर्थिक कहानी समेटे हुए है।यशोभूमि में प्रदर्शित 'सैंड से सिलिकॉन से सिस्टम' मूल्य श्रृंखला यह दिखाती है कि भारत की महत्वाकांक्षा केवल किसी एक फैब या पैकेजिंग इकाई तक सीमित नहीं है।लक्ष्य एक ऐसा व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है,जिसमें डिजाइनर, इंजीनियर,निर्माता,उपकरण कंपनियाँ,कच्चे माल के उत्पादक, शोध संस्थान,स्टार्टअप और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनाने वाली कंपनियाँ एक-दूसरे से जुड़ें।यहीं से विकसित भारत 2047 का सपना सेमीकॉन इंडिया 2026 से जुड़ता है।

2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा।उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसकी वैश्विक तकनीकी भूमिका क्या होगी और उसके युवाओं के पास किस प्रकार के रोजगार होंगे,इन प्रश्नों के उत्तर आज की नीतियों और निवेश से तैयार होंगे।सेमीकंडक्टर क्षेत्र इस भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक उद्योग नहीं,बल्कि अनेक उद्योगों की आधारभूत तकनीक है।प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत की इस यात्रा को नई गति मिलने की बात कही और यह भी रेखांकित किया कि भारत ने कुछ ही वर्षों में वह प्रगति की है,जिसमें सामान्यत: अधिक लंबा समय लगता है। उन्होंने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला बताया।साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान एवं विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और भारत तथा विदेशों में शोध कर रहे युवा वैज्ञानिकों और प्रतिभाओं को देश की उन्नत तकनीकी यात्रा से जुड़ने का आग्रह किया।युवा इंजीनियर इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं।सेमीकंडक्टर उद्योग में केवल पूंजी लगाने से कारखाना खड़ा नहीं होता। इसके लिए डिजाइन इंजीनियर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, सामग्री वैज्ञानिक,उपकरण इंजीनियर,सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, पैकेजिंग विशेषज्ञ,परीक्षण विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता चाहिए।यही कारण है कि सेमीकॉन इंडिया 2026 में वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और छात्र हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों को भी स्थान दिया गया है।लगभग 40 स्टार्टअप वाला स्टार्टअप पवेलियन भी यह संदेश देता है कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा केवल बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को चिप डिजाइन का प्रशिक्षण दिए जाने और उन्हें स्वयं चिप डिजाइन करने के अवसर मिलने की चर्चा की।यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग की शिक्षा अब केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह सकती।भारत को ऐसे इंजीनियर चाहिए जो समस्या को समझें,डिजाइन तैयार करें, प्रयोग करें,असफल हों और फिर नया समाधान विकसित करें। प्रयोगशाला से उद्योग और उद्योग से बाजार तक जाने वाली यही संस्कृति विकसित भारत की तकनीकी नींव बनेगी।सेमीकॉन 2.0 इसी दिशा में अगला कदम है।इस कार्यक्रम का जोर केवल बड़े सिलिकॉन फैब पर नहीं, बल्कि डिजाइन,विशेषीकृत फैब, उन्नत पैकेजिंग,उपकरण एवं घटक निर्माण,कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा निर्माण जैसे क्षेत्रों पर है। यानी सरकार अब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की दिशा में बढ़ रही है। कार्यक्रम में चिप डिजाइन, उपकरण और सामग्री से लेकर अनुसंधान और कौशल तक अनेक स्तरों को समर्थन देने की व्यवस्था की गई है।इसका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से है।भारत को यदि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे उच्च मूल्य वाले विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। सेवा क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दी है,लेकिन आने वाले समय में विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स,सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन,हरित ऊर्जा,अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र आर्थिक विकास के नए इंजन बन सकते हैं।सेमीकंडक्टर इन सभी क्षेत्रों के बीच एक साझा कड़ी है।

एक चिप केवल एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक नहीं है। इसके पीछे डिजाइन सॉफ्टवेयर से लेकर अत्यंत शुद्ध सामग्री,विशेष मशीनें,रसायन, गैसें, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, पैकेजिंग तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूरी श्रृंखला होती है।इसलिए भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार होने का अर्थ हजारों प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ उससे जुड़े अनेक सहायक उद्योगों, सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास भी है।इसीलिए सेमीकॉन इंडिया 2026 को रोजगार और युवा उद्यमिता के दृष्टिकोण से भी देखना आवश्यक है।अतीत के आने वाले वर्षों में चिप डिजाइन,एम्बेडेड सिस्टम,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स,ऑटोमेशन,इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्र में नई विशेषज्ञता की मांग बढ़ेगी।भारत के इंजीनियरिंग संस्थानों के सामने यह अवसर है कि वे अपने पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं को भविष्य की इन जरूरतों से जोड़ें।प्रधानमंत्री ने उद्योग से अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी अधिक सक्रियता से लेने का आह्वान भी इसी संदर्भ में किया।भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि शोध को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुँचाने की गति कैसे बढ़ाई जाए। यदि विश्वविद्यालय में तैयार तकनीक उद्योग तक नहीं पहुँचती और उद्योग की समस्या शोध संस्थानों तक नहीं पहुँचती,तो दोनों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में यह दूरी और भी कम करनी होगी। भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलता परिदृश्य भी एक अवसर लेकर आया है।दुनिया अब ऐसे नए और भरोसेमंद स्थान चाहती है जहाँ महत्वपूर्ण तकनीकों का उत्पादन विविधीकृत रूप में किया जा सके।प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया को चिप निर्माण के लिए नए और भरोसेमंद स्थानों की आवश्यकता है और भारत स्वयं को एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।इस अवसर का लाभ केवल निवेश आकर्षित करके नहीं उठाया जा सकता।इसके लिए गुणवत्ता,समयबद्ध उत्पादन, विश्वसनीय ऊर्जा,पानी, लॉजिस्टिक्स,कुशल मानव संसाधन और अनुसंधान की मजबूत व्यवस्था चाहिए। .भारत में समर्पित माल गलियारों, औद्योगिक गलियारों, बंदरगाहों और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार इसी व्यापक औद्योगिक व्यवस्था का हिस्सा है। आधुनिक चिप उद्योग को जिस प्रकार की जटिल आपूर्ति श्रृंखला चाहिए, उसके लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढाँचा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस पूरी कहानी को और बड़ा बना रही है।एआई के लिए उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग,डेटा सेंटर और उन्नत चिप की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर सेमीकंडक्टर उद्योग स्वयं एआई आधारित डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण तकनीकों से लाभ उठा सकता है।यानी एआई और सेमीकंडक्टर एक-दूसरे को गति देने वाले क्षेत्र बन सकते हैं।भारत यदि दोनों क्षेत्रों में अपनी युवा प्रतिभा को पर्याप्त अवसर देता है तो विकसित भारत की अर्थव्यवस्था में उच्च तकनीकी उद्योगों का महत्व और बढ़ सकता है।

स्टार्टअप इस परिवर्तन के तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।सेमीकॉन इंडिया 2026 में लगभग 40 स्टार्टअप की भागीदारी यह बताती है कि चिप उद्योग का भविष्य केवल कुछ वैश्विक दिग्गज कंपनियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। चिप डिजाइन, सेंसर,इलेक्ट्रॉनिक्स,एम्बेडेड सिस्टम,परीक्षण और विशिष्ट औद्योगिक समाधान के क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यम भी अपनी जगह बना सकते हैं।सेमीकॉन 2.0 में चिप डिजाइन स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए वित्तीय तथा तकनीकी समर्थन की व्यवस्था इसी दिशा में है।यहाँ भारत की युवा शक्ति को एक नया अवसर दिखाई देता है।

संपादकीय

स्कूल के शूल

पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का वह वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका बच्चे को डांटती और थप्पड़ मारती नज़र आ रही थी। उसके बाद बच्चे को कटे पेड़ की तरह गिरते देखा गया। बताते हैं कि होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने एलकेजी के छह वर्षीय छात्र प्रणय तेजा को पहले बुरी तरह डांटा और फिर उसे जोर से थप्पड़ मारा, जो उसे एक शॉक की तरह लगा। सीसीटीवी कैमरे की पुलिस द्वारा हासिल रिकॉर्डिंग में बच्चे की पिटाई और जमीन पर गिरने का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। जहां बताया गया है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चा घर से स्वस्थ स्थिति में स्कूल के लिए निकला था। उसे कोई रोग भी नहीं था। बाकायदा उसने स्कूल जाने की खुद जिद की। उसके पिता के अनुसार उनका परिवार एक तीर्थयात्रा पर गया था, जिसकी वजह से वह होमवर्क नहीं कर सका। इसके बाद टीचर के खिलाफ कार्रवाई और निजी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने और संवेदनशील व्यवहार की मांग तेज हुई। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने दलील दी कि खेल के मैदान में गिरने की वजह से बच्चे की जान गई। बताया जाता है कि स्कूल में कोई खेल का मैदान था ही नहीं। पूरी दुनिया में ऐसे तमाम अध्ययन व शोध निष्कर्ष सामने आ चुके हैं कि स्कूली बच्चों का किसी भी तरह शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल शिक्षकों का शैक्षिक दायित्व है बल्कि वे इसके लिये कानूनी रूप से भी बाध्य हैं। लेकिन विडंबना यह है कि शिक्षकों ने जाने क्यों मान लिया है कि किसी छात्र की गलती को दंडित या प्रताड़ित करके ही सुधारा जा सकता है। कहीं न कहीं यह शिक्षकों में धैर्य व तार्किक सोच की कमी को भी दर्शाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले दिनों ऐसी ही घटना सामने आई। वहां विनोद नगर में एक सरकारी स्कूल की ग्यारह साल की छात्रा की सजा दिए जाने के बाद मौत हो गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह क्लास में किताब लाना भूल गई। शिक्षिका ने उसे क्लास के पीछे हाथ ऊपर करके खड़े होने की सजा दी। कक्षा में इस तरह काफी देर तक खड़े रहने और अपमान से आहत होने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। इसी तरह की अन्य घटना में फरीदाबाद के एक स्कूल में मामूली बात पर छात्रा को चार घंटे खड़े होने की सजा दी गई। घटना से आहत व अपमानित महसूस करके छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी। आखिर कई स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि उन्हें छात्रों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। वे क्यों नहीं सोचते कि क्लास में सबके सामने दंडित किए जाने से बच्चे के कोमल मन-मस्तिष्क पर कैसा नकारात्मक असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस बाबत सभी दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अप्रिय हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कई शिक्षक इन कानूनी व नैतिक मापदंडों को ताक पर रखकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। निस्संदेह, कोई भी शैक्षिक व्यवस्था किसी भी शिक्षक को निरंकुश व्यवहार करने और अपनी भड़ास निकालने की इजाजत नहीं देती। दरअसल, समय के साथ-साथ बच्चों में ऐसे भाव विकसित हो गए हैं कि वे कक्षा में सार्वजनिक रूप से अपमान व प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करते। समाज में एकल परिवार परंपरा के प्रचलन के बाद बच्चे अभिभावकों के ध्यान के केंद्र में आ गए हैं।

न्याय की भाषा अब जनभाषा बनेगी

(लेखक – कांतिलाल मांडोत)

सुप्रीम कोर्ट की 'जन सूचना सेवा' से आसान हिंदी में समझ आएगा फैसलों का सार

हिंदी दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुरू की गई 'जन सूचना सेवा' को न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के और करीब लाने वाला ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य निर्णय माना जाना चाहिए। न्यायपालिका के महत्वपूर्ण फैसले अक्सर कानूनी शब्दावली और जटिल भाषा में होते हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि अदालत ने वास्तव में क्या फैसला दिया, उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे उसे क्या करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की नई पहल इस दूरी को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 'जन सूचना सेवा' के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चुने हुए महत्वपूर्ण आदेशों और फैसलों का सरल एवं सहज हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि न्यायालय की भाषा और आम आदमी की समझ के बीच जो अंतर है, उसे कम किया जा सकेगा। कई बार अदालत का फैसला किसी व्यक्ति के अधिकार, संपत्ति, रोजगार, शिक्षा, परिवार या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा होता है, लेकिन कानूनी भाषा की जटिलता के कारण संबंधित व्यक्ति स्वयं यह नहीं समझ पाता कि निर्णय का वास्तविक अर्थ क्या है। नई व्यवस्था में केवल लिखित जानकारी तक सीमित रहने के बजाय हिंदी में ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। करीब 15 से 30 मिनट के इन बुलेटिन के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाई जाएगी। यह पहल उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है, जो अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिन्हें कानूनी भाषा समझने में कठिनाई होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्याय की जानकारी केवल पढ़े-लिखे वर्ग तक सीमित न रहकर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। अदालत का फैसला केवल कागज पर लिखा हुआ आदेश नहीं होता। उसके पीछे किसी व्यक्ति के अधिकार, वर्षों की कानूनी लड़ाई और परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसलिए फैसला आने के बाद उसका अर्थ समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब सरल हिंदी में फैसले का सार मिलने से सामान्य नागरिक यह जान सकेगा कि अदालत ने क्या कहा है और उस निर्णय का व्यावहारिक अर्थ क्या है। इससे लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कानूनी मामलों में भाषा की कठिनाई के कारण पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अदालतों की प्रक्रिया और कानूनी शब्दावली समझना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। कई बार लोग अपने मामले की सामान्य जानकारी के लिए भी वकीलों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों पर निर्भर होते हैं। मुकदमों में पहले से ही आर्थिक और मानसिक दबाव झेल रहे लोगों को छोटी-छोटी बातों की जानकारी के लिए भी भारी खर्च करना पड़ सकता है। यह कहना उचित होगा कि 'जन सूचना सेवा' लोगों की इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक उपयोगी प्रयास है। हालांकि कानूनी सलाह की आवश्यकता अपने स्थान पर बनी रहेगी, लेकिन फैसले का सामान्य अर्थ समझने के लिए नागरिक को हर बार किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस पहल का महत्व निरक्षर और कम पढ़े-लिखे लोगों के संदर्भ में और बढ़ जाता है। लिखित फैसला पढ़ना उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यदि उसी निर्णय की जानकारी सरल हिंदी में सुनने और देखने के माध्यम से मिले तो वे भी न्यायालय के निर्णय को समझने की स्थिति में आ सकते हैं। ऑडियो और वीडियो माध्यम इस दृष्टि से बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। न्याय की जानकारी केवल अदालतों और कानून के जानकारों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही किसी भी लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस सेवा की शुरुआत हिंदी से की है और आगे इसे अन्य भारतीय भाषाओं में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। यह कदम भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। देश में भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं और लोगों की अभिव्यक्ति के तरीके भी अलग-अलग हैं, लेकिन न्याय सभी के लिए समान है। इसलिए न्याय की जानकारी भी ऐसी भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए जिसे नागरिक आसानी से समझ सकें। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भाषाएं अनेक रहें, लेकिन भावना भारतीय हो और बोलियां अनेक रहें, लेकिन आवाज एक हो। हिंदी शब्द-सिंधु जैसे ऑनलाइन शब्दकोश में स्थानीय भाषाओं और बोलियों के हजारों शब्दों को शामिल किया जाना हिंदी को अधिक व्यापक और लचीला बनाने की दिशा में प्रयास है। हिंदी को केवल साहित्य और संवाद की भाषा के रूप में नहीं, बल्कि शासन, न्याय और जनसंचार की प्रभावी भाषा के रूप में विकसित करने के प्रयासों का अपना महत्व है। पिछले वर्षों में सरकार ने भी जनसामान्य तक शासन और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग बढ़ाया है। सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन विस्तार, भारतीय भाषाओं में सूचना उपलब्ध कराने, डिजिटल माध्यमों से नागरिकों को जोड़ने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं। इसी व्यापक बदलाव के बीच सुप्रीम कोर्ट की 'जन सूचना सेवा' न्यायिक जानकारी को जनसुलभ बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आई है। न्याय तभी अधिक प्रभावी रूप से जनन्याय बन सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों और अदालत के निर्णयों को समझ सके। कानून का ज्ञान केवल विशेषज्ञों की संपत्ति नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन को किसी फैसले से प्रभावित होना है, उसे यह जानने का अधिकार है कि उसके बारे में अदालत ने क्या कहा है। सरल हिंदी में फैसलों का सार और ऑडियो-वीडियो माध्यम इस अधिकार को व्यवहार में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम हैं।

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल इसलिए भी ऐतिहासिक कही जा सकती है क्योंकि यह न्यायपालिका और आम नागरिक के बीच संवाद को अधिक सहज बनाने का प्रयास है। आने वाले समय में यदि यही सुविधा देश की प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी विस्तार पाती है तो इसका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। न्याय की गरिमा बनी रहे और उसकी भाषा आम आदमी की समझ से बाहर न हो, इस संतुलन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। 'जन सूचना सेवा' इसी आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। यह केवल हिंदी दिवस की घोषणा नहीं, बल्कि न्याय को अधिक सरल, सुलभ और जनोन्मुख बनाने की दिशा में उठाया गया ऐसा कदम है, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सकता है।

आत्मा का दिव्य भाव

जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणों में से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वत: विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब चेतना कृष्ण में स्थानान्तरित कर देता है, तो इन्द्रियतृप्ति स्वत: रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे भौतिक शरीर के आदेशों के पालन की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगी। वह न तो शरीर का भोग करना चाहती है, न उससे बाहर जाना चाहती है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान-अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति ऐसे मिथ्या मान-अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह इसकी चिन्ता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है, जो कृष्णभावनामृत में उसके कर्त्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन में उसकी सहायता करता है, मित्र मानता है और तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भलीभांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ लेना-देना नहीं है।

0.4 फीसदी का छोटा शुल्क, विशाल लेन- देन, लाखों करोड़ की कमाई?

(लेखक – सनत जैन)

भारत सरकार ने यूपीआई शुल्क लगाने की जो घोषणा की है उसके बाद से देश में बवाल मच गया है। पिछले 12 वर्षों से लगातार टैक्स बढ़ाई जा रही है। हर सेवा और हर वस्तु पर टैक्स लग रहा है। जिसके कारण आम आदमी टैक्स से बहुत परेशान हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था, तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे। लोगों के पास टैक्स देने को पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने बड़ी तेजी के साथ उस समय विकास किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। भारत की तुलना में दक्षिण कोरिया ने बड़ी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति की। उन कारणों को जानना भी जरूरी है। दोनों देशों ने लगभग एक ही दौर में नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने कुछ दशकों में औद्योगिक और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। 1948 से 1960 के दशक में साउथ कोरिया में हर ट्रांजैक्शन पर एक फ़ीसदी टैक्स हर किसी से वसूल किया जाता था। सरकार ने बैंकों से साउथ कोरिया के नागरिकों को इसी अवधि में बिना ब्याज के, बिना गारंटी के छोटे-छोटे लोन देना शुरू किये। लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित करने, नागरिकता खत्म कर, नागरिक सुविधा से बाहर करने का कानून बनाया। साउथ कोरिया ने 65 फ़ीसदी स्टेट ड्यूटी का प्रावधान किया, जिसके कारण साउथ कोरिया की आर्थिक और सामाजिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ बेहतर हुई। ऐसा माना जाता है एक फ़ीसदी न्यूनतम टैक्स होने के कारण साउथ कोरिया में टेक्स की चोरी नहीं हुई। 65 फ़ीसदी स्टेट ड्यूटी होने के कारण लोगों ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी सुविधाओं पर खर्च किया। 16-18 साल के युवा अपने बेहतर भविष्य को लेकर जो काम कर सकते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्हें काम करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा था। इस बदलाव से 1960 के बाद कानून में बदलाव हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई। 1960 से 1969 के बीच साउथ कोरिया की जीडीपी 7.6 फ़ीसदी से आगे बढ़ रही थी। 1970 से 1979 के बीच में औद्योगिक विकास बढ़कर 8.4 फ़ीसदी को पार कर गया। सारी दुनिया में साउथ कोरिया का डंका बजने लगा। इसके पीछे साउथ कोरिया सरकार द्वारा समय-समय पर जो परिवर्तन किये गये इसका असर अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था मे नैतिकता के रूप में भी देखने को मिला।

यहीं से भारत के लिए एक बड़ा सवाल निकलता है। लेन-देन पर छोटा-सा शुल्क लगाकर बहुत बड़ा राजस्व या आर्थिक संसाधन बनाया जा सकता है? इसका जवाब है, हां। यदि सरकार हर ट्रांजेक्शन पर शुल्क लेने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति पर अन्य कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी तब कहा था कि सारे अन्य टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी का शुल्क बढ़ा दिया गया, लेकिन एक भी टैक्स खत्म नहीं हुआ उल्टे हर सेवा और हर वस्तु पर सरकार ने टैक्स लगा दिया। पिछले 10 से 12 सालों में जिस तरह से टैक्स और शुल्क के मकड़जाल मे फंसकर आम जनता कराह रही है, इसी बीच सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसे सरकार कर नहीं बल्कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बता रही है। इसका पैसा सीधे सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं यूपीआई के हिस्सेदारों में वितरित होगा। यूपीआई की सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों के पास 80 फ़ीसदी से ज्यादा लेन-देन है। निश्चित रूप से इसका फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिलने जा रहा है।

इसके लेनदेन का आकार बहुत बड़ा है। अगस्त 2026 में यूपीआई से लगभग 24.5 अरब लेन-देन हुए हैं। उनका कुल मूल्य करीब 29.82 लाख करोड़ है। यदि उदाहरण के लिए पूरे इस वॉल्यूम पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है, तो यह गणना लगभग 11,929 करोड़ दिखाई देती है। यह उदाहरण बताता है कि छोटी प्रतिशत की दर और विशाल आर्थिक वॉल्यूम मिलकर बहुत बड़ा वित्तीय बाजार बना सकते हैं। यही इस व्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक प्रश्न है। दक्षिण कोरिया की कर प्रणाली का वास्तविक सबक भी यही है। कर की दर से ज्यादा महत्वपूर्ण कर-संग्रह की व्यापकता, धन का उत्पादक उपयोग, वित्तीय व्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ना है। वहां सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को उद्योग और निर्यात के विस्तार के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया है। वहां का कोई उद्योगपति दिवालिया नहीं होता है। बैंक का कर्ज ईमानदारी के साथ चुकाता है। भारत में इसके ठीक विपरीत स्थिति है। भारत में दिवालिया कानून का उपयोग बैंकों का कर्ज हड़पने के रूप में हो रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टाटा संस की कमान 5 साल और संभालेंगे एन चंद्रशेखरन

बोर्ड ने दूसरे कार्यकाल को मंजूरी दी

नई दिल्ली।

टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहे एन चंद्रशेखरन अगले पांच साल भी टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। टाटा संस के बोर्ड ने गुरुवार को उनके नए कार्यकाल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की आगे की रणनीति और विस्तार को जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप के शीर्ष पद से अपने सफर की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने 1987 में ज़ष्टस् में इंटर्न के तौर पर करियर शुरू किया था। करीब तीन दशक बाद वे समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन बने और अब उनके नेतृत्व का एक और पांच साल का दौर शुरू होने जा रहा है। 2017 में संभाली थी टाटा संस की कमान चंद्रशेखरन ने 2017 में टाटा संस के चेयरमैन का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में ग्रुप ने पारंपरिक कारोबार के साथ कई नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया। एविएशन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और डिजिटल बिजनेस जैसे क्षेत्रों में टाटा ग्रुप की गतिविधियां बढ़ीं। यानी समूह की रणनीति सिर्फ मौजूदा कंपनियों के कारोबार को बढ़ाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि भविष्य के उद्योगों में भी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर रहा।

करमतारा इंजीनियरिंग का शेयर 26 फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं बिजली पारेषण क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग इस्पात उत्पाद बनाने वाली करमतारा इंजीनियरिंग का शेयर अपने 254 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 26 प्रतिशत की बढ़त के साथ गुरुवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। कंपनी के शेयर ने बीएसई और एनएसई दोनों पर 320 रुपये पर कारोबार शुरू किया, जो निर्गम मूल्य से 25.98 प्रतिशत की बढ़त है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 11,326.55 करोड़ रुपये रहा। करमतारा इंजीनियरिंग के 875 करोड़ रुपये के आईपीओ को पिछले सप्ताह शुक्रवार को शेयर बिक्री के अंतिम दिन 62.63 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ का मूल्य दायरा 241-254 रुपये प्रति शेयर था। करमतारा इंजीनियरिंग ने बड़े (एंकर) निवेशकों से 262.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

करमतारा इंजीनियरिंग घरेलू एवं विदेशी बाजारों के लिए पारेषण लाइन टावर, सौर ढांचे तथा ट्रैकर कलपुर्जों, पवन ऊर्जा ढांचों, संरचनात्मक इस्पात 'प्रोफाइल' और 'फास्टनर' सहित विभिन्न इंजीनियरिंग इस्पात उत्पादों का विनिर्माण करती है।

रूस पर अमेरिकी शिकंजा- तेल खरीदारों पर टैरिफ का अधिकार, भारत-चीन पर पड़ेगा असर

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी

वाशिंगटन।

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के कानून बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं, पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। बुधवार शाम 262-159 वोटों से पारित हुए लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को अब राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य रूस के राजनीतिक नेतृत्व और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों को और कड़ा करना है। इसमें रूस की शैडो फ्लीट पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल मॉस्को प्रतिबंधों से बचते हुए तेल बेचने के लिए करता है। विधेयक में राष्ट्रपति को उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने का भी प्रस्ताव है, जो रूसी तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसका सीधा असर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने इन देशों से रूस के बजाय अन्य स्रोतों से तेल खरीदने का आग्रह किया है।

यह विधेयक पहले ही अमेरिकी सीनेट में 86-11 वोटों के भारी बहुमत से पारित हो चुका था। प्रतिनिधि सभा में इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसदों का समर्थन मिला, हालांकि डेमोक्रेट्स के एक वर्ग ने राष्ट्रपति को अतिरिक्त टैरिफ अधिकार देने के प्रावधान पर आपत्ति जताई थी। प्रतिनिधि सभा में यह मतदान ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी संसद का मौजूदा सत्र नवंबर में होने वाले चुनावों से पहले अपने अंतिम चरण में है। ट्रंप की मंजूरी के बाद यह कानून रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर नए अमेरिकी टैरिफ का रास्ता खोल देगा।

शेयर बाजार सपाट बंद

सेंसेक्स 21 अंक गिरा, निफ्टी 53 उछल

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुआ। आज दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही जहां सेंसेक्स 22 अंक गिर, वहीं निफ्टी में हल्की बढ़त दर्ज की गयी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के परिणामों के आंकलन से भी घरेलू शेयर बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ा । इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 21.86 अंक नीचे आकर 74,314.59 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,270.60 पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान व्यापक बाजारों में निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.92 फीसदी और 0.76 फीसदी की तेजी रही। मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों का प्रदर्शन बेहतर बना रहा क्योंकि निवेशकों ने मजबूत कमाई की संभावना वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी, खासकर कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, पावर और हेल्थकेयर सेक्टर में।सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

निफ्टी50 इंडेक्स में एचडीएफसी लाइफ के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.05 फीसदी की तेजी रही। इसके साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी), एसबीआई लाइफ, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज, बीईएल, इंडिगो और टाटा स्टील के शेयर सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों की सूची में शामिल रहे। जबकि इसके विपरीत ओएनजीसी, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, कोल इंडिया औरनेस्ले इंडिया के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गयी।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को भारतीय रुपया 20 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.71 पर बंद हुआ। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों की कमजोर धारणा से रुपया शुरुआती कारोबार में 19 पैसे टूटकर 96 प्रति डॉलर से नीचे पहुंच गया। यह दो महीने से अधिक समय में पहली बार है जब रुपया इस स्तर से नीचे आया है। घरेलू मुद्रा ने हालांकि, बाद में शुरुआती गिरावट की कुछ भरपाई की और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप के बाद 10 पैसे की बढ़त के साथ कारोबार करने लगा। विदेशी मुद्रा बाजार के विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ऊंची बनी हुई हैं और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा भी मजबूत है। ऐसे में रुपये में काफी उतार-चढ़ाव रहने के आसार हैं।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.88 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में टूटकर 96.10 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 19 पैसे की गिरावट है। रुपया 24 जुलाई के बाद पहली बार 96 के स्तर से नीचे आया।

एचआर प्रैक्टिसेज के लिए एलजी इंडिया को दो पुरस्कार

कंपनी को 'टॉप ऑर्गनाइजेशन', सीएचओ ज्वा नाम किम को 'मोस्ट इम्पैक्टफुल एचआर लीडर' सम्मान

नई दिल्ली ।

बेंगलुरु में आयोजित 25वें एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड्स 2026 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को एचआर प्रैक्टिसेज के लिए दो पुरस्कार मिले। कंपनी को 'टॉप ऑर्गनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज' और उसके चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर (सीएचओ) ज्वा नाम किम को 'मोस्ट इम्पैक्टफुल एचआर लीडर' अवार्ड से सम्मानित किया गया। कंपनी के अनुसार, नेतृत्व विकास, संगठनात्मक क्षमता, कार्यस्थल संस्कृति, कर्मचारी अनुभव और टैलेंट डेवलपमेंट से जुड़ी पहलों के लिए यह सम्मान मिला। वहीं, ज्वा नाम किम को एचआर ट्रांसफॉर्मेशन और कर्मचारियों को बिजनेस ग्रोथ से जोड़ने में उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। ज्वा नाम किम ने कहा कि यह सम्मान एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के कर्मचारियों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कंपनी की एचआर रणनीति बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है और आगे नेतृत्व विकास, कर्मचारी क्षमताओं व संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत करने पर जोर रहेगा। कंपनी के मुताबिक, एलजी इंडिया को 2024 और 2025 में लगातार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन मिला है। उसे नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026, मोस्ट इनोवेटिव एलएंडडी प्रोग्राम अवार्ड 2026 और एचआर डिस्टिंक्शन डायमंड सम्मान भी मिल चुके हैं। ज्वा नाम किम को इससे पहले 'टॉप एचआर आइकॉनिक लीडर' अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

अमेरिकी विधेयक से भारत पर संकट, रूसी तेल खरीद पर 100 फीसदी शुल्क का खतरा

विशेषज्ञ बोले- ऊर्जा सुरक्षा से समझौता न करे भारत

नई दिल्ली ।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल एवं गैस खरीदने वाले देशों, विशेषकर भारत, पर 100 प्रतिशत तक का भारी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने इस कदम को भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बताया है और चेताया है कि इसका वास्तविक असर अमेरिकी शुल्क की दरों और उत्पादों के दायरे की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नामक यह विधेयक बुधवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा से 262-159 मतों से पारित हुआ है। इससे पहले सीनेट इसे पिछले महीने ही मंजूरी दे चुकी थी।

अब यह कानून राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उन्हें चीन, भारत और अन्य देशों पर कड़े शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों को रूसी तेल एवं गैस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मजबूर करना है। जीटीआरआई के अनुसार, यह कानून राष्ट्रपति को रूस के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जिसके संभावित निशाने पर भारत और चीन हैं। जीटीआरआई ने आगाह किया कि यह नया अमेरिकी कानून प्रतिबंधों को भारत के खिलाफ एक व्यापार हथियार में बदल देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका 100 प्रतिशत तक

शुल्क लगाने की धमकी देगा और फिर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद कम करने तथा बेहद असमान द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत रियायतें स्वीकार करने पर कम शुल्क की पेशकश करेगा। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता न करने की सलाह दी। उन्होंने जोर दिया कि रियायती रूसी कच्चे तेल ने भारत की आयात लागत को कम किया है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद की है।

जब तक रूसी तेल व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहता है, भारत को उसकी खरीद जारी रखनी चाहिए और एकतरफा व्यापार रियायतें दिए बिना अमेरिका के साथ मजबूती से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अमेरिकी कार्रवाइयों से बचने के लिए कोई भी व्यापार समझौता या रूसी तेल खरीद रोकना पर्याप्त नहीं होगा।

इंडिगो ने बच्चों के किराए, लगेज व अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ाए

– दो साल से कम उम्र के बच्चों का किराया सीधे 1,000 रुपये बढ़ा

अहमदाबाद।

घरेलू हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए हवाई किराए और विभिन्न सेवाओं के शुल्कों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इंडिगो ने दो साल से कम उम्र के बच्चों के किराए में सीधा 1,000 रुपये का इजाफा किया है। अब माता-पिता को अपनी गोद में बच्चे को ले जाने के लिए 2,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये चुकाने होंगे, भले ही उन्हें अलग सीट आवंटित न की जाए। इस बढ़ोतरी से एयरलाइन को सालाना लगभग 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है, क्योंकि देशभर में हर साल 10 लाख से अधिक शिशु हवाई यात्रा करते हैं। किराए के अलावा, इंडिगो ने अन्य सेवाओं के शुल्क में भी वृद्धि की है। घरेलू उड़ानों पर अतिरिक्त सामान का शुल्क 700 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही, अकेले यात्रा करने वाले बच्चों का शुल्क 5,000 रुपये से बढ़कर 5,999 रुपये और प्राथमिकता चेक-इन व बोर्डिंग का शुल्क 450 रुपये से 650 रुपये हो गया है। ट्रेवल सर्टिफिकेट जैसे अन्य शुल्कों में भी वृद्धि की गई है।

एनएसई का मेगा आईपीओ खुला, पहले दिन 9 फीसदी अभिदान मिला

नई दिल्ली ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) का 22,569 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) गुरुवार को अभिदान के लिए खुल गया है। बोली के पहले दिन इसे कुल नौ प्रतिशत अभिदान मिला, जो इस वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है। बीएसई आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत श्रेणी में 15 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में 12 प्रतिशत बोली लगी।

इससे पहले एनएसई ने बुधवार को एलआईसी, गोल्डमैन सैक्स और फिडेलिटी जैसे प्रमुख एंकर निवेशकों से 6,746 करोड़ रुपए जुटाए। सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी सिंगापुर और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इनमें शामिल थे। मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 12.64 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश वाला यह निर्गम हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। एनएसई ने प्रति शेयर 1,700-1,785 रुपए का मूल्य दायरा रखा है।

एनएसई आईपीओ बाजार में दबदबा,आय पर दबाव का साया

खुदरा निवेशकों के लिए खुला इश्यू; उच्च मूल्यांकन, घटते डेरिवेटिव वॉल्यूम से पैदा हुई चिंताएं

नई दिल्ली।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) गुरुवार से खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है। हालांकि, घटते डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम और उच्च मूल्यांकन के कारण निवेशकों में सतर्कता का माहौल है, क्योंकि नियामक परिवर्तनों से इसकी कमाई पर असर पड़ा है। एनएसई आईपीओ का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2027-28 की अनुमानित कमाई के 35-38 गुना पर है, जो वैश्विक एक्सचेंजों से कहीं अधिक है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कमी के चलते मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष में परिचालन राजस्व 3.1 फीसदी और मुनाफा 15.5 फीसदी गिर गया। बाजार हिस्सेदारी में एनएसई बेहद मजबूत है, कैश-मार्केट टर्नओवर में 92.99 फीसदी और इक्विटी फ्यूचर्स में 99.79 फीसदी हिस्सेदारी है। जून 2026 तिमाही में 4,560 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और 3,121 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। हालांकि, एनएसई राजस्व का 80 फीसदी ट्रेडिंग से (जिसमें 60 फीसदी ऑप्शंस से आता है) प्राप्त करता है। नए नियमों के कारण ऑप्शंस वॉल्यूम 27 फीसदी तक गिरे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नियामक उपायों से वित्त वर्ष 27 में वृद्धि लगभग 5

फीसदी तक धीमी रह सकती है। खुदरा निवेशकों को अब यह तय करना है कि वे आईपीओ में दांव लगाएं या लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदें।

एमडीआर लागू होने से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग उद्योग की आय में होगी बढ़ोतरी?

वित्त वर्ष 2027-28 में करीब 180 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान

नई दिल्ली।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर छह साल बाद एक बार फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग उद्योग की आय में 15,000 से 20,600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज कंपनियों ने लगाया है।

एमडीआर वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए दुकानदारों से लिया जाता है। एमडीआर 2,000 रुपए से ज्यादा के पीयर-टु-मर्चेंट (पी2एम) यानी ग्राहक से कारोबारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लागू होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 26 अगस्त के लेनदेन स्तर को आधार मानें तो कुल यूपीआई पी2एम लेनदेन मूल्य का करीब 48 फीसदी हिस्सा एमडीआर के दायरे में आता है।

इससे उद्योग के लिए करीब 20,600 करोड़ रुपए की आय का मौका है। सिटी ने सालाना 16 से 17 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया है। वहीं, जेफरीज ने उद्योग के लिए 15 से 18 हजार करोड़ रुपए की आय का होने की संभावना जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमडीआर से होने वाली आय यूपीआई व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पक्षों के बीच बांटी जाएगी। इनमें पीएसपी बैंक, यूपीआई ऐप प्रदाता के साथ वे दोनों बैंक शामिल हैं जिनसे रकम निकलेगी और जिनमें रकम पहुंचेगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक कुल आय में से 50 फीसदी हिस्सा भुगतान जारी करने वाले बैंकों और पीएसपी को, 20 फीसदी थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता को और 30 फीसदी भुगतान लेने वाले बैंकों को मिलेगा।

सिटी के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त आय का करीब 60 फीसदी हिस्सा जारी करने वाले और लेने वाले बैंकों या यूपीआई हैंडल के जरिये बैंकिंग क्षेत्र को मिलेगा। करीब 25 फीसदी आय यूपीआई ऐप प्रदाताओं और बाकी 15 फीसदी गैर-बैंक पेमेंट एग्रीगेटरों को मिलने की संभावना है।

लोन जमा नहीं होने पर बैंक या एनबीएफसी गाड़ी को जबरदस्ती नहीं उठा सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-गाड़ी जब्त करने से पहले तय प्रक्रिया का पालन करना होगा

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक या एनबीएफसी को गाड़ी वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वे इसके लिए मनमाना या जबरदस्ती का तरीका नहीं अपना सकते। गाड़ी जब्त करने से पहले तय प्रक्रिया और उचित नोटिस का पालन करना होगा यानी सिर्फ ईएमआई नहीं भरने का मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी रात में गाड़ी उठाकर ले जाए। बता दें यह मामला यूपी के एक ट्रक मालिक से जुड़ा है। उसने कमर्शियल ट्रक खरीदने के लिए चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। कुछ समय बाद वह किस्तें नहीं चुका पाया।

कंपनी ने नोटिस दिया और ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। बाद में ग्राहक ने एकमुश्त रकम जमा की तो उसे ट्रक वापस मिल गया। इसके बाद फिर लोन की किस्तें नहीं चुकाई गईं। ग्राहक के मुताबिक 9 अप्रैल 2023 की रात करीब एक बजे अयोध्या में सामान पहुंचाने के बाद खड़े ट्रक का स्टीयरिंग लॉक चार अज्ञात लोगों ने तोड़ा और ट्रक लेकर चले गए। उसका कहना था कि उसे इस कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं दिया गया था1 बाद में ट्रक बेच दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि फाइनेंसर के पास लोन की शर्तों के तहत गाड़ी वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी बल प्रयोग करके या चोरी-छिपे वाहन कब्जे में ले सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा। रात में ताला तोड़ना, जबरदस्ती गाड़ी ले जाना या लोगों के जरिए दबाव बनाना सही तरीका नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में कंपनी को ग्राहक के अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। आरबीआई के पुराने दिशानिर्देशों में भी लोन वसूली के दौरान ग्राहक को अनावश्यक रूप से परेशान करने, गलत समय पर संपर्क करने और बल प्रयोग करने से बचने को कहा गया है।

भारत प्रमुख बाजार, चिप क्षेत्र वृद्धि के लिए तैयार-इन्फिनियॉन

नई दिल्ली ।

जर्मनी की सेमीकंडक्टर कंपनी इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजीज के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने भारत को एक 'बेहद महत्वपूर्ण' बाजार बताया है। उन्होंने कहा कि देश का चिप परिवेश आर्थिक वृद्धि, उद्योग के विस्तार और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के दम पर एक नए तथा रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहा है। 'सेमीकॉन इंडिया 2026' में बोलते हुए हैनेबेक ने कहा कि इन्फिनियॉन का भारत में भरोसा अटूट है, और देश वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। कंपनी 1,200 से अधिक ग्राहकों के साथ काम करती है, और भारत की तेजी से हो रही प्रगति तथा वैश्विक नवाचार में योगदान से प्रभावित है। इन्फिनियॉन 25 साल से अधिक समय से भारत में है। उसने पिछले एक साल में अपने कर्मचारियों की संख्या 28 प्रतिशत बढ़ाकर 2,800 से अधिक कर दी है, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु व हैदराबाद में कार्यरत हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की सगाई टूटी

मंगेतर आकृति अग्रवाल ने अलग होने की घोषणा की

मुंबई । भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ निजी जिदंगी भी मुश्किलों से गुजर रही है। पृथ्वी एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पृथ्वी की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अलग होने की जानकारी साझा की है। आकृति ने इंस्टाग्राम के जरिए पृथ्वी शॉ से अलग होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'भारी मन से, मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अपने भविष्य के लिए अलग-अलग लक्ष्यों और हालात की वजह से अलग होने का फैसला किया है। हम एक-दूसरे से जितना प्यार और परवाह करते हैं, हमने यह मान लिया है कि हमारे रास्ते साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। अपनी जिम्मेदारियों और अभी जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। ' आकृति ने आगे लिखा, 'मैं सच में हम दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी शांति और खुशी की कामना करती हूं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस मुश्किल समय में हमारी निजता का सम्मान करें और हमारे फैसले के पीछे के कारणों के बारे में अंदाजा लगाने से बचें। हमारी जगह को समझने और उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद। '

पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च, 2026 को सगाई की थी। पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें आ रही थीं। आकृति के सोशल मीडिया पोस्ट ने उस पर मुहर लगा दी है।

26 साल के पृथ्वी शॉ को एक समय भारतीय क्रिकेट का अगला तेंदुलकर माना जा रहा था। 2018 में मात्र 18 साल की उम्र में शॉ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और शतक लगाया था। हालांकि, बाद में उनके फॉर्म में गिरावट आई और वे टीम से बाहर हो गए। फिलहाल उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी अपनी जगह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

डब्ल्यूबीबीएल के 12वें सीजन में भी मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलेंगी डिएंड्रा डॉटिन

मेलबर्न । आगामी विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) सीजन से पहले मेलबर्न रेनेगेड्स को बड़ी राहत मिली है। वेस्टइंडीज की स्टार ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन ने एक और सीजन टीम रेनेगेड्स की तरफ से खेलने की पुष्टि की है। टी20 क्रिकेट की सबसे दमदार ऑलराउंडरों में से एक मानी जाने वाली डॉटिन डब्ल्यूबीबीएल 11 में टीम के सभी मैचों में खेलने के बाद रेनेगेड्स के साथ अपना तीसरा सीजन शुरू करेंगी। उनकी वापसी रेनेगेड्स द्वारा वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज के साथ फिर से करार करने के बाद हुई है।

इस जोड़ी ने डब्ल्यूबीबीएल 10 में मेलबर्न की पहली डब्ल्यूबीबीएल खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी और अब आगामी सीजन के लिए वे फिर से एक साथ (रेड जर्सी में) खेलेंगी। चोट के कारण मैथ्यूज डब्ल्यूबीबीएल के 11वें सीजन नहीं खेल पाई थीं, जबकि डॉटिन रेनेगेड्स के अभियान का अहम हिस्सा बनी रहीं।

मेलबर्न रेनेगेड्स के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर क्लिंट मैके ने डॉटिन की वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि वेस्टइंडीज की यह स्टार खिलाड़ी टीम में काफी अनुभव और मैच जिताने की काबिलियत लाएगी। मैके ने कहा, डिएंड्रा दुनिया की सबसे असरदार खिलाड़ियों में से एक हैं और हम मेलबर्न रेनेगेड्स में उनकी वापसी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं।

चोट से वापसी के बाद आत्मविश्वास की जरूरत होती है: नीतीश रेड्डी

नई दिल्ली । अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में चोट से वापसी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी को एक बड़ा बूस्ट मिला। नीतीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। सीरीज के पहले मैच में औसत प्रदर्शन के बाद, नीतीश ने कहा कि दूसरे मैच में मिले अच्छे प्रदर्शन से उन्हें वह आत्मविश्वास

मिला जिसकी उन्हें वापसी के दौरान जरूरत थी। नीतीश ने बुधवार को बीसीसीआई के एक वीडियो में कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। चोट से वापसी करने वाले हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास की जरूरत होती है। सच कहूं तो, पहला मैच मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन दूसरे मैच में अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को ऐसे आत्मविश्वास की जरूरत होती है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस आत्मविश्वास को आगे भी बनाए रखूंगा।' नीतीश ने 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए भारत को अफगानिस्तान को 159/8 पर रोकने और फिर 7 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल करने में मदद की। 22 वर्षीय खिलाड़ी का यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय आया, जब उन्होंने हाल ही में बताया था कि फिटनेस हासिल करने के लिए उन्होंने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कड़ी मेहनत की थी।

सिंधु का नाम कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर के रूप में दर्ज है।

2017 में कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली

सिंधु बनीं भारत की पहली खिलाड़ी

नई दिल्ली । भारतीय बैडमिंटन की दुनिया में मौजूदा समय का सबसे बड़ा नाम पीवी सिंधु का है। सिंधु ने अपने बेहतरीन खेल की वैश्विक मंचों पर सफलता हासिल करते हुए देश का नाम रोशन किया है। दो ओलंपिक पदक जीत चुकी सिंधु का नाम कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर के रूप में दर्ज है। 17 सितंबर 2017 को पीवी सिंधु कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थीं। सिंधु ने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को एक घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में 22-20, 21-11 और 21-18 से हराकर खिताब जीता था। 1991 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के 26 साल के इतिहास में सिंधु भारत की तरफ से पहली विजेता बनी थीं। हालांकि, इस सफलता से पहले ही सिंधु अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सफल बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुकी थीं।

5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में जन्मी सिंधु ने बैडमिंटन की दुनिया में बड़ी सफलता हासिल की है। वह भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सिंधु की उपलब्धियों पर गौर करें तो उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2019 में वह महिला एकल में विश्व चैंपियन रही थीं। 2018 और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। सिंधु ने 2018 एशियन गेम्स में रजत और 2014 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली और इकलौती भारतीय हैं और ओलंपिक गेम्स में लगातार दो मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं। 31 साल की सिंधु का एक बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर सफर अभी भी जारी है। भारत सरकार पीवी सिंधु को बैडमिंटन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण, और पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है।

एशियन गेम्स 2026

फातिमा सना की कप्तानी पारी

थाईलैंड को हराकर पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट

निशिन । पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 3 विकेट से हराया। झमाझम बारिश के चलते गीली आउटफील्ड के कारण इस मैच को 11-11 ओवर का किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड की बल्लेबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा। उन्होंने 11 ओवर में 4 विकेट खोकर 91 रन

स्कोरोबोर्ड पर लगाए। टीम की तरफ से नानापत कोंचारोएनकाई ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 49 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके लगाए। वहीं, फन्निता माया ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए, जबकि कप्तान नारुएमोल चाईवाई ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में कप्तान फातिमा सना का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 3 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि नशरा संधू ने एक विकेट अपने नाम किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम को गुल फिरोजा और शवाल जुल्फिकार ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 3.5 ओवर में 36 रन जोड़े। फिरोजा 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, जुल्फिकार ने 178 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 14 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 25 रन बनाए। आयशा जाफर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और एक रन बनाकर आउट हुईं। पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम अचानक से बुरी तरह से लड़खड़ा गया और टीम ने 11 रन जोड़कर अपने 4 विकेट गंवा दिए।

6 शतक और 500 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी

नई दिल्ली, । भारत के दिग्गज स्पिनर्स का जब जिक्र होता है, तो उस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन का नाम भी शान से लिया जाता है। अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर में वो तमाम उपलब्धियां हासिल कीं, जिसका सपना एक क्रिकेटर देखता है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 और 300 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज रहे।

अश्विन का जन्म 17 सितंबर, 1986 को चेन्नई में हुआ। अश्विन के पिता खुद एक मध्यम गति के गेंदबाज थे और पिता को देखकर ही अश्विन क्रिकेट से परिचित हुए। धीरे-धीरे अश्विन का लगाव क्रिकेट के प्रति बढ़ता चला गया। अश्विन अपने करियर की शुरुआत में सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे।

हालांकि, 14 वर्ष की उम्र में अश्विन बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें काफी समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इसके बाद अश्विन ने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की, तो सलामी बल्लेबाज की

जगह भर चुकी थी। मां के कहने पर अश्विन ने स्पिन गेंदबाजी में हाथ आजमाए और जल्द ही वह इसमें रम गए।

अश्विन ने इसके बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2010 में उन्हें भारतीय टीम से बुलावा आया। जिम्बाब्वे के खिलाफ अश्विन ने वनडे फॉर्मेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। वहीं, क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में अश्विन को डेब्यू करने का मौका 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिला। अश्विन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के बूते जल्द ही भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली।

अश्विन विश्व कप 2011 में चैंपियन बनी भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। वहीं, 2013 में उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। अश्विन ने भारत के लिए खेले 106 टेस्ट मैचों में कुल 537 विकेट चटकाए।

पाकिस्तान का नया ड्रामा

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी टीम को भारत भेजने से किया इनकार, न्यूट्रल वेन्यू की मांग

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने भारत के साथ 'संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति' का हवाला देते हुए बुधवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के लिए अपनी पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) से टूर्नामेंट या उसके सभी मुकाबलों को न्यूट्रल वेन्यू पर स्थानांतरित करने का

अनुरोध किया। पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने कहा कि वह पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की निर्बाध और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल चाहता है। बता दें कि यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक मोहाली और जालंधर में आयोजित किया जाएगा। पीएचएफ के अंतरिम अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट या पाकिस्तान के सभी मुकाबलों को न्यूट्रल वेन्यू पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

इशान किशन नंबर 1

अभिषेक शर्मा टॉप-5 में, 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले फुल मेंबर्स टीम के शीर्ष-10 बैटर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले (ये आंकड़े आईसीसी के फुल मेंबर्स टीम के खिलाड़ियों के ही हैं) बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। इशान किशन ने इस मामले में शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ दिया जबकि इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा टॉप-5 में शामिल हैं। इशान किशन ने साल 2026 में अब तक क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट,वनडे,टी20आई) को मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 52 छक्के लगाए हैं और वो खबर लिखे जाने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं।

ज्यादा छक्के

इशान किशन- 52 छक्के
शिमरोन हेटमायर- 50 छक्के
हैरी ब्रुक- 48 छक्के
अभिषेक शर्मा- 42 छक्के
डेवाल्ड ब्रेविस- 37 छक्के
शिवम दुबे- 34 छक्के
कॉनर एस्टरहुइजेन- 32 छक्के
संजू सैमसन- 32 छक्के
दासुन शनाका- 30 छक्के
तंजीद हसन- 30 छक्के
शेरफेन रदरफोर्ड- 28 छक्के
फिन एलन- 26 छक्के

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मधुमेह से बचाव में फायदेमंद होती है खड़े रहने की आदत

अक्सर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए चहलकदमी और व्यायाम का सुझाव दिया जाता है, लेकिन इस मामले में खड़े रहने की आदत भी मददगार साबित हो सकती है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2

फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर

रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

खराब इंसुलिन प्रणाली मधुमेह की वजह

एनर्जी मेटाबॉलिज्म और रक्त शर्करा के नियमन में इंसुलिन एक प्रमुख हार्मोन है। कई बार वजन अधिक होने से शरीर में इंसुलिन के सामान्य फंक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है और टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 मधुमेह दुनियाभर में सबसे आम जीवनशैली की बीमारियों में से एक है। इसकी शुरुआत आमतौर पर बिगड़ी हुई इंसुलिन संवेदनशीलता या इंसुलिन प्रतिरोध से होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें शरीर सामान्य रूप से इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2 मधुमेह से बचाव के मामले में खड़े रहना फायदेमंद होता है। फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता के बीच संबंध पाया गया है। इतना ही नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

गतिहीन व्यवहार से इंसुलिन प्रणाली प्रभावित

जीवनशैली का इंसुलिन में रुकावट और टाइप 2 मधुमेह के विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं की रोकथाम में नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अब तक इंसुलिन की रुकावट पर गतिहीन व्यवहार, लगातार बैठे रहने के बीच ब्रेक और खड़े रहने की आदत के प्रभावों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तुर्कू पीईटी सेंटर और यूकेके संस्थान के हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंसुलिन में बाधा और गतिहीन व्यवहार के बीच संबंध की जांच की। इसके

निष्क्रियता के साथ टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों के विकास के बढ़ते जोखिमों को भी देखा।

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि रोजमर्रा की नियमित शारीरिक गतिविधि या बैठने के समय, फिटनेस स्तर से अलग स्वतंत्र रूप से खड़े रनहा बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा

एवं तुर्कू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तारू गर्थवेट का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्ष रोजाना बैठने के समय के एक हिस्से में लोगों को खड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगे। खासकर अगर शारीरिक गतिविधि की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह तरीका मददगार हो सकता है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम होगी

भी जोर देता है। अध्ययन परिणाम बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस या बैठने में लगने वाले समय की तुलना में शरीर में वसा के प्रतिशत में इजाफा इंसुलिन संवेदनशीलता के मामले में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी ओर खड़े होना शरीर की संरचना के बावजूद इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि नियमित व्यायाम को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है।

मगर ऐसा लगता है कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस और गतिहीन व्यवहार भी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन परोक्ष रूप से यह शरीर की संरचना पर उनके प्रभाव के माध्यम से जुड़े हैं। जर्नल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इन स्पोर्ट में प्रकाशित इस अध्ययन के आधार पर अभी तक कारण प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार परिणाम बताते हैं कि यदि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं की जा रहीं तो रोजाना खड़े होने का समय बढ़ाने से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

कम नींद लेने से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां

कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमरियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज्यादा भारतीय सोचते हैं कि नींद लेना कोई प्राथमिकता नहीं है। पिछले कुछ सालों में नींद के महत्व और आवश्यक नींद पूरी न होने से जुड़े खतरों के बारे में बताए जाने के बाद भी लोग नींद को उतनी अहमियत नहीं देते जितना कि व्यायाम को देते हैं। हाल ही में देशभर में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में नींद की कमी गंभीर चिंता का कारण क्यों है?

यहां तक देखा गया है कि लोगों को यह कहने में फख्र महसूस होता है कि वे 4-5 घंटे ही सोते हैं और अपने बाकी के सभी कामों को प्राथमिकता से करते हैं। यदि इस तरह के कम सोने वाले लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय व घर-परिवार में कुशल हों तब तो ऐसे लोगों का उदाहरण दूसरे लोगों के लिए पेश किया जाता है कि 'देखो फलाना व्यक्ति ज्यादा सोने में समय बर्बाद नहीं करता है इसलिए तो उसने जीवन में इतना कुछ पा लिया है।'

यह बात और है कि आगे जाकर कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमरियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं। हमारे देश में कई लोग आज भी ऐसे हैं, जो ये मानते हैं कि खर्राटे आना गहरी नींद की निशानी है। उन्हें यह समझाना चुनौतीपूर्ण काम है कि दरअसल खर्राटे आना भी एक गंभीर नींद विकारों के कारणों में से एक है।

एक अन्य हाल ही के सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 19 फीसदी भारतीय वयस्कों की नींद में बाधा का कारण उनके काम करने की शिफ्ट का बदलते रहना है। 32% युवा वयस्क टेक्नोलॉजी के ज्यादा और देर रात तक प्रयोग की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते हैं।

एक वयस्क के लिए भी 7 से 9 घंटे की नींद बेहद जरूरी है। कई मामलों में जो लोग इतना सोते हैं उन्हें देखकर अन्य लोग ऐसे लोगों के लिए राय बना लेते हैं कि 'फलाना व्यक्ति आलसी व कमजोर है', तो कुछ लोगों को तो खुद ही यह कहने में शर्म महसूस होती है कि 'उन्हें इतना सोने की जरूरत है।' सिर्फ 1 दिन यदि आप 4-5 घंटे से कम सोते हैं, तब आपके शरीर की वे प्राकृतिक कोशिकाएं, जो कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म करने में सक्षम होती हैं, 70% तक कम हो जाती हैं। आपको कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं आपके शरीर में प्रतिदिन बनती हैं। रिपोर्ट के अनुसार नींद की कमी से आंत, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप प्रतिदिन नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर उठें।

क्यों नहीं आती है आपको मीठी नींद

दिनभर की मेहनत और थकान के बाद एक सुहानी नींद पर आपका पूरा हक है लेकिन कई लोगों को बेवजह नींद न आने की शिकायत होती है। आइए मीठी नींद के लिए क्या करें जतन.

- रोज सुबह उठकर कसरत करनी चाहिए।
- अच्छी नींद लेने के लिए कभी भी दिन में न सोएं और सोने से कुछ देर पहले एल्कोहल या कैफीन का सेवन भूलकर भी न करें।
- धूम्रपान न करने से भी नींद अच्छी आती है क्योंकि सिगरेट में पाए जाने वाला निकोटिन नींद में बाधा उत्पन्न करता है।
- कई प्रकार के ड्रग्स भी आराम की नींद लेने में बाधक सिद्ध होते हैं।
- अगर आप शाम को कसरत करेंगे तो आपको सोने में परेशानी हो सकती है।
- जिन महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है उन्हें अक्सर नींद कम आती है। इसलिए शरीर में आयरन की कमी का विशेष ख्याल रखें।
- सुबह जब आप उठें तो सूर्य की तेज रोशनी को कमरे में अंदर आने दें। क्योंकि सही प्रकाश की वजह से शरीर को सही ऊर्जा मिलती है।
- एक बात और ध्यान रखें कि रात को सोते वक्त बेडरूम में रोशनी कम ही रहनी चाहिए, जिससे अच्छी और भरपूर नींद आ सके।

...तो जनाब अच्छी व गहरी नींद लीजिए और फिर जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जी लेने के लिए खुद को तैयार पाइए।

सूखा नारियल सेहत के लिए है कुदरत का वरदान

सूखे नारियल का इस्तेमाल घरों में खीर, आइसक्रीम, स्वीट डिश वगैरह में होता है। ज्यादातर लोग इसे स्वाद बढ़ाने के लिए रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इस बात पर कम लोगों का ध्यान जाता है। नारियल आपके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसे चबाने से फेशियल एक्सरसाइज भी होती है। इसमें ऐंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं।

ऐंटीऑक्सिडेंट्स का भंडार

नारियल में फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि ऐंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी सेल्स के ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। इसमें गैलिक एसिड, कैफिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पी-कोम्यूरिक एसिड होता है। नारियल आपकी धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है जो कि हार्ट ब्लॉकेज की वजह होती हैं।

कनेक्टिव टिशूज के लिए फायदेमंद

नारियल में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके कनेक्टिव टिशूज को मजबूत बनाते हैं। नारियल को डायट में शामिल करने से गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं होने का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है।

आयरन की कमी को दूर करता है

महिलाओं में आयरन की कमी बड़ी समस्या है। सूखे नारियल में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। डेली डायट में नारियल खाने से आयरन की कमी पूरी होती है। बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं को नारियल की कई मिठाइयां इसीलिए बनाकर खिलाई जाती हैं।

पोषकतत्वों का भंडार

सूखे नारियल में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और सेलिनियम पाया जाता है। ये पोषक तत्व इम्यूनिटी मजबूत करके शरीर को रोगों से बचाते हैं।

दिमाग रखता है मजबूत

नारियल खाने से किसी का आईक्यू तो नहीं बदलता लेकिन आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। स्टडीज में सामने आ चुका है कि नारियल का तेल अल्जाइमर्स होने से रोकता है।

सेहत का रखना है ख्याल तो अर्जुन फल का करें इस्तेमाल

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें।

अर्जुन के वृक्ष को भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद ही गुणकारी माना गया है। दरअसल, इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल जैसे विभिन्न औषधीय गुण होते हैं। अर्जुन हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करता है और हृदय के समुचित कार्य में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह उच्च रक्तचाप से लेकर दस्त, अस्थमा और खांसी आदि कई तरह की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अर्जुन के फल से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

सांसों की दुर्गंध से मिलता है छुटकारा

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें। इस फल में ऐसे होते हैं जो आपके मसूड़ों की समस्याओं और दांतों से खून बहने में भी मदद कर सकते हैं और आपको ताजा सांसें प्रदान करते हैं।

हड्डियों का रखते हैं ख्याल

अगर आप किसी किसी भी प्रकार की हड्डी की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार में अर्जुन फल को अवश्य शामिल करना चाहिए। आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या इसे कच्चा खा सकते हैं। यह आपको ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डियों की परेशानी में भी मदद कर सकता है।

ओरल हेल्थ की समस्याओं को करें दूर

अर्जुन फल खाने से वास्तव में आपकी मसूड़ों की समस्याओं को कम करने और दांतों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। यह दांतों से खून बहने से लेकर दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द या मसूड़ों से खून बहना आदि समस्याओं के उपचार में प्रभावी है। आप इस फल को जूस या कच्चा खा सकते हैं। इसके अलावा, अर्जुन के फल के पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट के रूप में उस जगह पर लगा सकते हैं जहां आपको मसूड़े या दांतों की समस्या हो रही है। हालांकि, यह उपाय अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

सेंधा नमक को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

सेंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सेंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है।

नमक एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जिसका इस्तेमाल हम सभी नियमित रूप से करते हैं। यह भोजन में एक स्वाद शामिल करता है। नमक के बिना भोजन पकाने या उसे खाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि घरों में लोग टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नमक को अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाना चाहते हैं तो आज ही सेंधा नमक खाना शुरू कर दें। सेंधा नमक में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सेंधा नमक का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह स्वस्थ त्वचा और बालों से लेकर वजन घटाने तक कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। सेंधा नमक से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

पाचन तंत्र के लिए लाभदायक

सेंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सेंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है। यह भूख की कमी की समस्या को सुधारने में भी मदद करता है।

प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है

सेंधा नमक विटामिन के से भरपूर होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह शरीर की हड्डियों के चयापचय को भी बढ़ाता है, जो कई बीमारियों से बचाता है। मांसपेशियों में ऐंठन से राहत सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड का शुद्ध रूप और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम और नमक असंतुलन मांसपेशियों में ऐंठन के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। तो, सेंधा नमक पोटेशियम की कमी को संतुलित कर सकता है और मांसपेशियों में ऐंठन को रोक सकता है।

गले की खराश का करता है इलाज

गले में खराश के लिए खारे पानी से गरारे करना एक आम घरेलू उपाय है। सेंधा नमक में डिकॉन्गेस्टेंट गुण होते हैं जो आपकी बंद नाक, खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। यह टॉन्सिलिटिस अस्थमा के लिए भी एक प्रसिद्ध उपाय है, और यह आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

रक्तचाप को करे बैलेंस

सेंधा नमक में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि सेंधा नमक रक्तचाप को संतुलित रखता है।

संक्षिप्त समाचार

लंदन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का कार्यक्रम रद्द

लंदन , एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ब्रिटेन दौरे पर हैं। मंगलवार को लंदन में उनका एक कार्यक्रम सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया। लंदन की द शार्ड इमारत के बाहर सैकड़ों प्रशंसक जमा हुए थे। कार्यक्रम रद्द होने से घंटों से इंतजार कर रहे कई प्रशंसक निराश हुए। मुख्यमंत्री का दल तमिलनाडु में निवेश आकर्षित करने यूके के दौरे पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में 12,300 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस निवेश अभियान का लक्ष्य तमिलनाडु को एशिया का उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना है। इससे राज्य भर में 9,400 से अधिक उच्च-मूल्य वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। विजय बुधवार को अपना यूके दौरा समाप्त कर भारत लौटेंगे।

कांगो में तीसरे कार्यकाल के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

किंशासा , एजेंसी। अफ्रीकी देश कांगो में राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी के तीसरे कार्यकाल की संभावना वाले सांविधानिक परिवर्तनों के खिलाफ मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। विपक्षी गठबंधन सी64 ने किंशासा समेत कई शहरों में ये प्रदर्शन आयोजित किए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुए पर सरकार समर्थक समर्थकों से झड़प के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। विपक्षी नेता मार्टिन फायुलु ने सरकार पर राजनीतिक मिलिशिया के साथ काम करने का आरोप लगाया। कांगो सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मुयाया ने विपक्ष की निंदा की, कहा विरोध का अधिकार सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए। कांगो का संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा में बदलाव पर रोक लगाता है। नेशनल असेंबली में एक विधेयक विचाराधीन है, जो राष्ट्रपति को इन प्रावधानों को बदलने की अनुमति दे सकता है। त्सेसीकेदी के सत्ता में बने रहने के प्रयास का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों ने मई में सी64 का गठन किया था।

2 हेलिकॉप्टर, 21 विमान और 50 घंटे... ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चला खतरनाक मिशन

वाशिंगटन, एजेंसी। सोचिए, आपका फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में गिर चुका है, पैराशूट ठीक से नहीं खुला और शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है. नीचे जमीन पर दुश्मन की सेना आपको खोज रही है और आपके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. ऐसे में अगर मदद का भरोसा हो भी, तो सवाल यही है कि वह मदद आप तक पहुंचेगी कैसे? अप्रैल 2026 में ईरान में अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. स्र-15श्व फाइटर जेट के गिरने के बाद उसके दो क्रू मेंबर अलग-अलग जगह जा गिरे. अप्रैल में अमेरिकी स्र-15श्व स्ट्राइक ईगल ईरान के ऊपर एक मिशन पर था. इसी दौरान विमान को एक मिसाइल से निशाना बनाया गया और वह क्रैश हो गया. विमान में दो अमेरिकी अधिकारी थे, जिन्हें यहां उनके कॉल साइन 'अल्फा' और 'ब्रावो' से जाना गया और विमान ईरान में ही जा गिरा था. दोनों ने विमान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पहुंचने के बाद उनकी लोकेशन अलग हो गई।

ट्रंप ने अपने पसंदीदा सिंगर की पत्नी को बनाया राजदूत उम्मीदवार, बारबाडोस-पूर्वी कैरिबियन की संभालेंगी जिम्मेदारी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा और मशहूर देशभक्ति गीत 'गॉड ब्लेस द यूएसए' के सिंगर ली ग्रीनवुड की पत्नी किम्बर्ली ग्रीनवुड को बारबाडोस और पूर्वी कैरेबियाई देशों के लिए अमेरिकी राजदूत के पद के लिए नामित किया है. ट्रंप प्रशासन ने किम्बर्ली के अलावा और भी कई अन्य राजदूत पदों के लिए नामित लोगों की लिस्ट अमेरिकी सीनेट के पास भेजी है. किम्बर्ली ग्रीनवुड की नियुक्ति के लिए अब सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी. अगर अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो किम्बर्ली बारबाडोस के साथ-साथ सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस जैसे कैरेबियाई देशों में एक साथ अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवाएं देंगी।

बाइडन ने रोकी थी खेप, ट्रंप ने की जारी: इस्राइल को 40 हजार खतरनाक बम देगा अमेरिका

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रंप प्रशासन 2.8 अरब डॉलर के प्रस्तावित हथियार सौदे के तहत इस्राइल को 40,000 शक्तिशाली 2,000 पाउंड के बम देने की तैयारी कर रहा है। इनमें 20,000 एमके-84 और 20,000 बीएलयू-117 बम शामिल हैं। यह वही श्रेणी के हथियार हैं जिनकी एक खेप बाइडन प्रशासन ने 2024 में गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिकों के हताहत होने की आशंका के चलते रोक दी थी। प्रस्तावित सौदा ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा में युद्ध को लेकर इस्राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा हुआ है और युद्धविराम के बावजूद हिंसा जारी है।

40 हजार बमों का प्रस्तावित सौदा : अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 2.8 अरब डॉलर के इस पैकेज में कुल 40,000 बम शामिल हैं। इनमें 20,000 एमके-84 और 20,000 बीएलयू-117 बम हैं। दो अमेरिकी अधिकारियों और इस योजना से परिचित एक व्यक्ति ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इन सभी ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बात की, क्योंकि हथियारों का यह पैकेज अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है।

कांग्रेस को दी गई सौदे की जानकारी : अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तावित हथियार सौदे के बारे में अनौपचारिक रूप से जानकारी दे दी गई है। इस सौदे की बड़ी राशि विदेशी सैन्य वित्त पोषण के जरिए चुकाई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका इस्राइल को सैन्य सहायता के लिए धन देता है और इस्राइल उसी धन से अमेरिका से हथियार खरीदता है।

इस्राइल की सैन्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम : यह प्रस्तावित सौदा ट्रंप प्रशासन की ओर से इस्राइल की सैन्य क्षमता मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में नया कदम है। गाजा में लंबे समय से जारी संघर्ष में दसियों हजार फलस्तीनियों की मौत हुई है और पूरा इलाका बुरी तरह तबाह हुआ है। अमेरिका की मध्यस्थता से एक नाजुक युद्धविराम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा जारी रही है।

गाजा युद्ध के बीच बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव : यह हथियार सौदा ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा में युद्ध को लेकर इस्राइल को बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के घातक हमले के जवाब में इस्राइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद से इस्राइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा है।

ईरान संघर्ष के बावजूद कायम है अमेरिका-इस्राइल गठजोड़ : प्रस्तावित हथियार सौदा यह संकेत देता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंधों में आए कुछ तनाव के बावजूद दोनों देशों का सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ मजबूत बना हुआ है। खास तौर पर फरवरी में दोनों देशों द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किए जाने के बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ मतभेद सामने आए थे। ट्रंप और नेतन्याहू के संबंधों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ईरान संघर्ष को लेकर ट्रंप ने जुलाई में व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से अपनी मुलाकात से पहले उनसे जुड़ी कुछ बातों पर नाराजगी भी जाहिर की थी।

बाइडन ने रोकी थी बमों की एक खेप : 2024 में बाइडन प्रशासन ने इन 2,000 पाउंड के बमों की एक खेप इस्राइल को भेजने से रोक दी थी। हालांकि, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने उस रोक को हटा दिया। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस की सामान्य समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इस्राइल के साथ करीब 3 अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी दी थी। इसमें 35,500 से अधिक बम शामिल थे। इसके बाद जनवरी में ट्रंप प्रशासन ने इस्राइल के लिए हथियारों की नई श्रृंखला को मंजूरी दी, जिसकी कुल कीमत 6.67 अरब डॉलर थी।

2,000 पाउंड के बम कितने शक्तिशाली हैं : 2,000 पाउंड के बमों के कई अलग-अलग संस्करण हैं। इनमें कुछ ऐसे बम हैं जिन्हें जमीन के भीतर मौजूद या भूमिगत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, कुछ संस्करण जमीन के ऊपर विस्फोट करते हैं और बड़े इलाके में व्यापक तबाही मचा सकते हैं।

गाजा में अमेरिकी बमों के इस्तेमाल के सबूत : इस्राइली सेना ने गाजा में इस्तेमाल किए गए बमों और तोपों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है। हालांकि, हमले के वीडियो फुटेज और घटनास्थलों से मिले विस्फोटक अवशेषों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा में अमेरिका निर्मित इन बमों का इस्तेमाल किया गया है।

बढ़ते युद्धों और हिंसक टकरावों के बीच शान्ति में निवेश की पुकार

जिनेवा, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर में बढ़ती हिंसा, विभाजन और हिंसक टकरावों के बीच विश्व नेताओं से शान्ति में निवेश बढ़ाने की अपील की है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय परिसर में जापानी शान्ति की घंटी बजाने के वार्षिक समारोह को सम्बोधित करते हुए यह सन्देश दिया.उन्होंने कहा, 'हर साल शान्ति घंटी की गूँज हमें हमारी सबसे अहम ज़िम्मेदारी की याद दिलाती है - शान्ति स्थापना की. 'शान्ति पर संकटउन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 'शान्ति अपने आप हासिल नहीं होती.' इसके लिए लगातार मेहनत और ठोस कार्रवाई की ज़रूरत होती है. लेकिन मौजूदा दौर में शान्ति के प्रयास कमज़ोर पड़ रहे हैं.उन्होंने कहा, 'हिंसा और विभाजन समुदायों को तोड़ रहे हैं. हिंसक टकराव फैल रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं. लोग पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए ज़रूरी संवाद और एकजुटता नदारद हैं. ' महासचिव की यह अपील 21 सितम्बर को मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय शान्ति दिवस से पहले आई है. इस वर्ष इसकी थीम है - 'शान्ति में निवेश: सर्वजन के लिए, हर जगह, हर दिन.'आमजन दिखा रहे हैं राहउन्होंने दुनिया भर के स्वयंसेवकों, पैरोकारों, नागरिक समाज के नेताओं, शान्तिरक्षकों और शान्ति के लिए काम कर रहे लोगों का उल्लेख किया, जो इस थीम को ज़मीनी स्तर पर साकार कर रहे हैं.उन्होंने कहा, 'जहाँ सरकारें शान्ति क़ायम करने में विफल हो रही हैं, वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठाकर, दूरियाँ कम करके और समुदायों को फिर से जोड़कर एक अलग रास्ता दिखा रहे हैं. 'महासचिव ने आने वाले हफ़्तों में संयुक्त राष्ट्र में जुटने वाले विश्व नेताओं से इन लोगों से प्रेरणा लेने और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व सामाजिक सुरक्षा में निवेश बढ़ाने की अपील की. साथ ही उन्होंने ऐसी संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, जिन पर लोग भरोसा कर सकें.एकजुटता, कार्रवाई और निवेशउन्होंने कहा कि नेताओं को मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा की रक्षा करनी होगी.

साथ ही, कूटनीति, संवाद, वार्ता और शान्तिरक्षा जैसे 'शान्ति के कारगर साधनों' के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होकर युद्धों एवं हिंसक टकरावों को समाप्त करना होगा.महासचिव ने कहा, 'आज मैं विश्व नेताओं से हमारे साथ खड़े होने की अपील करता हूँ - कार्रवाई करें, समाधानों में निवेश करें और स्थाई शान्ति स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

जोहान्सबर्ग में 7वीं महिला की लाश मिलने से हड़कंप

जोहान्सबर्ग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पूर्वी इलाके में मंगलवार को एक और महिला का शव मिलने के बाद लोगों में डर बढ़ गया है। पिछले 2 महीनों में इसी इलाके में कई महिलाओं के शव मिल चुके हैं। मंगलवार को मिले शव के साथ ऐसे मामलों की संख्या 7 हो गई है। लगातार हो रही इन मौतों के बाद किसी संभावित सीरियल किलर के इलाके में सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति है। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में कुछ समानताएं जरूर हैं और इसी वजह से जांच तेज करने के साथ महिलाओं के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा यानी कि स्रक्क ने महिलाओं से खास तौर पर सावधानी बरतने को कहा है। पुलिस ने इलाके में जॉगिंग जैसी गतिविधियों के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस प्रवक्ता एथलेंडा माठे ने कहा,

'जांच अभी जारी है और एसएपीएस ने इस समय तक यह पुष्टि नहीं की है कि इन मौतों का संबंध किसी सीरियल किलर से है। लेकिन मामलों में समानताएं इतनी चिंताजनक हैं कि पुलिस ने लोगों के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है और जांच को तेज कर दिया है।'

मंगलवार को मिला था महिला का शव : मंगलवार को एक महिला का शव क्वा-थेमा इलाके में मिला। यह जगह केंप्टन पार्क से करीब 34 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक, महिला का शव पूरी तरह नग्न अवस्था में मिला और वह काफी ज्यादा सड़-गल चुका था। इससे पहले सोमवार को ओलिफैंट्सन्टीन इलाके में भी एक महिला का शव बरामद हुआ था। इसके अलावा शनिवार को 38 साल की एलिजाबेथ 'सोंत्सो' मोसेलाकगोमो का शव मिला था। वह पिछले सप्ताह केंप्टन पार्क में जॉगिंग के लिए निकली थीं और उसके बाद लापता हो गई थीं। एलिजाबेथ की तलाश में स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया था और आखिरकार शनिवार को उनका अर्धनग्न शव बरामद हुआ। लगातार सामने आ रहे इन मामलों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी चिंता जताई है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इन हत्याओं की जांच को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

एच-1बी वीजा पर सख्ती: वेंस बोले- अमेरिकियों की नौकरियां नहीं छिनेंगी; काम के लिए देने होंगे एक करोड़ रुपये

वाशिंगटन डी.सी, एजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में सुधार के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों पर बात की है। इन प्रयासों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रोग्राम घरेलू पेशेवरों की जगह लेने के बजाय बेहतरीन काबिलियत वाले लोगों (टॉप-टियर टैलेंट) पर केंद्रित हो। लोकप्रिय बिजनेस और टेक्नोलॉजी शो 'ऑल-इन पॉडकास्ट' में बोलते हुए, वेंस ने राजनीतिक गतिरोध के कारण विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'देखिए, हमने सिस्टम में हो रही धोखाधड़ी पर गौर किया और सोचा कि एक तो कांग्रेस इसे बदलने वाला कोई कानून पास नहीं करने वाली है। ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति ही नहीं है। तो हम प्रशासनिक तौर पर क्या कर सकते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि अगर कोई टेक कंपनी एच-1बी वीजा हासिल करने की कोशिश करे, तो वह व्यक्ति सच में जीनियस हो।'

इस पहल के मकसद को लेकर क्या बोले : इस पहल के मुख्य मकसद के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह ऐसा व्यक्ति होगा, जो टेक इकोसिस्टम या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी बेहतर बनाएगा। आप जानते हैं, आप सिर्फ 60,000 डॉलर कमाने वाले एक अकाउंटेंट की जगह 45,000 डॉलर सालाना कमाने वाले कम वेतन वाले विदेशी अकाउंटेंट को नहीं रख रहे हैं। यह प्रोग्राम इस मकसद के लिए नहीं है। शुरू किए जा रहे खास वित्तीय और सुरक्षा उपायों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'इसलिए हमने 100,000 डॉलर का जुर्माना लगाने का विचार किया है। हम ऐसे तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं जिनसे एच-1 बी वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने से रोका जा सके। तो आप जानते हैं, मुझे इस बारे में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगती है कि कोई कंपनी एच-1बी के लिए अप्लाई करती है और कहती है, 'अरे, हमें कर्मचारियों की बहुत जरूरत है।'

कंपनियों की भर्ती प्रक्रियाओं में मौजूद विरोधाभासों को उजागर करते हुए वेंस ने कहा, 'हमें कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। और फिर आप उनके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने 5,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। यह तो अजीब बात है।' प्रशासन के कार्यबल विस्थापन पर रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आप अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, तो आपको उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों की तलाश में बाजार नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम कानूनी रूप से अनुमत सीमाओं के भीतर ही काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों में हम पर मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूल रूप से हम कानून और नीति दोनों के मामले में सही हैं। वीजा ढांचे के मूल उद्देश्य को दोहराते हुए उन्होंने कहा, 'एच-1बी वीजा का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों को कम वेतन वाले विदेशी कामगारों से बदलना नहीं होना चाहिए।

मक्का में पहली बार मिसाइल अटैक का इमरजेंसी अलर्ट : हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर हमला किया; 2017 में भी मक्का की ओर आई थी मिसाइल

मक्का, एजेंसी। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके बाद सऊदी अरब ने मक्का में पहली बार इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक, नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म ने अलर्ट जारी किया था। लोगों से ऊंची इमारतों से दूर रहने की अपील की गई। कुछ देर बाद सिविल डिफेंस ने बताया कि खतरा टल गया है। हालांकि, लोगों से भीड़ से दूर रहने और किसी घटना की वीडियो या फोटो नहीं बनाने की अपील की गई। मंगलवार सुबह जेद्दा और ताइफ में भी ऐसे ही इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए थे। इन्हें भी कुछ देर बाद वापस ले लिया गया। इससे पहले 27 जुलाई 2017 को हूती विद्रोहियों ने मक्का की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। लेकिन मिसाइल को मक्का से करीब 69 किलोमीटर दूर अल-वसिलिया इलाके में नष्ट कर दिया गया था।

लोगों से अपील- खुले इलाकों में जाने से बचें : मक्का, जेद्दा और ताइफ में जारी अलर्ट में लोगों से कहा गया कि वे भीड़ और खुले इलाकों में जाने से बचें। लोगों से शांत रहने और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई। लोगों को घर के अंदर रहने और खिड़कियों, बालकनी, छत, कांच और खुली जगहों से दूर रहने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर हो, तो उसे तुरंत पास की किसी बिल्डिंग में जाने या किसी मजबूत चीज की आड़ में छिपने और खतरा टलने तक वहीं रहने की सलाह दी गई है।

हूती हमलों में अब तक 86 लोग घायल : ये इमरजेंसी अलर्ट सऊदी अरब पर हूतियों के लगातार हमलों के बीच जारी किए गए हैं। सोमवार को हूतियों ने सऊदी शहरों खमिस मुशैत, अबहा और ताइफ की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागे थे। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलिकी के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम 13 नागरिक घायल हुए थे। मंगलवार को जारी बयान में अल-मलिकी ने सऊदी नागरिकों को निशाना बनाने वाले हूतियों के हमलों को जानबूझकर किया गया हमला बताया। पिछले हफ्ते भी हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन की बड़ी संख्या में हमले किए थे। इनमें अबहा, खमिस मुशैत, जाजान और नजरान शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में कम से कम 73 लोग घायल हुए थे। हमलों के बाद सऊदी अरब की कुछ ऊर्जा सुविधाओं का काम भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। ईरान से जुड़े हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब यमन में हवाई हमले कर रहा है और क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यमन के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हूती लड़ाकों और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच भारी लड़ाई चल रही है। इसी बीच हूतियों ने यमन के पश्चिमी लाल सागर तट पर तेजी से अपना कब्जा बढ़ाया है।

एफबीआई की नौकरी के नियम बदले?: सीनेट में उठे सवाल, काश पटेल ने पीड़ितों का दिया हवाला

वाशिंगटन, एजेंसी। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) निदेशक काश पटेल ने मंगलवार को एफबीआई के नौकरी से जुड़े नियमों में बदलाव का बचाव किया। ये बदलाव वेश्यावृत्ति और पशुओं के साथ यौन संबंध से जुड़े मामलों को लेकर किए गए हैं। पटेल ने कहा कि इन बदलावों का मकसद पीड़ितों की मदद करना है। ऐसे लोग भी एफबीआई में नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। उन्हें अपने पुराने अनुभव की वजह से अपने आप नौकरी के लिए अयोग्य न माना जाए। एफबीआई ने इस साल वसंत में चुपचाप अपने नियम बदले थे। पहले वेश्यावृत्ति में शामिल रह चुके लोगों पर नौकरी को लेकर पूरी रोक थी। ऐसे लोग एफबीआई में नौकरी के लिए अयोग्य माने जाते थे। अब यह रोक हटा दी गई है। कुछ मामलों में एफबीआई अब पूरे मामले की परिस्थितियों को देखेगा। ब्यूरो ने पशुओं के साथ यौन संबंध से जुड़े मामलों में भी ऐसा ही बदलाव किया है।

काश पटेल ने नियम बदलने की वजह क्या बताई : सीनेट की न्यायपालिका समिति की सुनवाई में पटेल से इन बदलावों के बारे में सवाल पूछे गए। पटेल ने कहा कि इससे नौकरी के मानक कम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव का मकसद पीड़ितों की रक्षा करना है। कुछ लोगों को जबरन ऐसे कामों में शामिल किया गया था। कुछ लोग मानव तस्करी के शिकार हुए थे। ऐसे लोगों को सिर्फ उनके साथ हुई घटना की वजह से नौकरी के लिए अपने आप अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। पटेल ने कहा कि एफबीआई पशुओं के साथ यौन संबंध के पीड़ितों को सजा नहीं देना चाहता था। उन्होंने मानव तस्करी के पीड़ितों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एफबीआई नहीं चाहता था कि ऐसे मामले अपने आप नौकरी से अयोग्य होने की वजह बन जाएं।

जॉन कैनेडी ने क्यों उठाए सवाल : पटेल के जवाब से रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी संतुष्ट नहीं हुए। कैनेडी लुइसियाना से सीनेटर हैं। उन्होंने पटेल से इस बदलाव के पीछे की वजह पूछी। पटेल ने बताया कि यह सुझाव उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने दिया था। कैनेडी ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पशुओं के साथ यौन संबंध से जुड़े नियम में बदलाव का सुझाव देने वाले व्यक्ति से पटेल ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वह किस ग्रह से आया है। पटेल ने जवाब दिया कि शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन बाद में उन्होंने इसे पीड़ितों की मदद करने का एक तरीका माना। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली समिति सुनवाई में पटेल के काम पर ध्यान देना चाहती थी। इसमें हिंसक अपराध से लड़ना शामिल था। ड्रग्स की तस्करी रोकना भी इसमें शामिल था।

पश्चिम एशिया तनाव: यूएस के हमले में ईरानी नावें तबाह; हूती लड़ाकों के हमलों के बीच सऊदी-मिस्र की नजदीकी बढ़ी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने इस हफ्ते ईरान की दो छोटी नावों पर गोली चलाई। इसके बाद दोनों नावों को नष्ट कर दिया गया। सेना के मुताबिक, ये नावें ईरान के पास समुद्र में एक बिना चालक वाले जहाज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थीं। यह छह महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध में दोनों पक्षों के बीच हुई ताजा झड़प है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी नावों ने हाल ही में एक अमेरिकी बिना चालक वाले समुद्री जहाज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुईं। अमेरिकी सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया।

ईरान के सरकारी मीडिया ने सोमवार को अलग जानकारी दी। उसने बताया कि ईरान के दक्षिणी तट पर होर्मोजगान प्रांत में मछली पकड़ने वाली दो नावों पर हमला हुआ। एक प्रांतीय अधिकारी के हवाले से कई मछुआरे लापता बताए गए। यह छह महीने से ज्यादा पुराने युद्ध में हुई ताजा गोलीबारी है। दोनों पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण चाहते हैं। यह दुनिया के लिए एक बेहद अहम ऊर्जा और तेल परिवहन मार्ग है। अमेरिका ने हाल के हफ्तों में इस मार्ग पर ईरान की पकड़ कुछ हद तक कमजोर की है। लेकिन इस

युद्ध का असर तेल और पेट्रोल की कीमतों पर पड़ा है। कीमतें बढ़ी हैं। यह संघर्ष अमेरिका में भी राजनीतिक समस्या बन रहा है। नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव होने हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही ईरान के साथ सैन्य संघर्ष खत्म होगा, तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को ओमान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। दोनों के बीच खाड़ी के अरब देश ओमान की कोशिशों पर चर्चा हुई। ओमान तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है।

हूती और सऊदी अरब के बीच संघर्ष बढ़ा : ईरान के समर्थन वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों का असर तेल की दुनिया पर भी पड़ा है।

हूती विद्रोही सऊदी अरब के जहाजों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। पश्चिम एशिया के संघर्ष में यह एक नया मोर्चा बन गया है। इससे सऊदी अरब के लिए अपना तेल दुनिया तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। कुछ दूसरे रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। कुछ मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं। कुछ दिन पहले सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर भी हमला हुआ था। इस हमले में पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। हूती विद्रोहियों की ताकत भी बढ़ी है। इससे उनके लिए लाल सागर के रास्ते सऊदी तेल के निर्यात को रोकना आसान हो सकता है। इस युद्ध का असर सिर्फ तेल पर नहीं पड़ा है। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। वाशिंगटन से आई नई रिपोर्ट्स में युद्ध पर अमेरिका के खर्च की जानकारी दी गई है। इनमें मिसाइलों को रोकने वाली उन्नत मिसाइलों के भंडार में कमी की जानकारी भी है। अमेरिकी विमानों, सैन्य ठिकानों और राजनयिक ठिकानों को हुए नुकसान का भी जिक्र है। गैर-दलीय कांग्रेस बजट कार्यालय यानी सीबीओ ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)